

₹
49/-

CULT CURRENT

हिंदी संस्करण

वर्ष: 8 अंक: 2 फरवरी, 2025

WE MAKE VIEWS



◀ 'सॉफ्ट हिंदुत्व'
या नया
पॉलिटिकल
ड्रामा ?



◀ क्वांटम टेलीपोर्टेशन:
एक अद्भुत
वैज्ञानिक
उपलब्धि



◀ अंतर्द में बांग्लादेश
क्या आवाजी
लीग फिर से उठ
खड़ी होगी?



ट्रम्प 2.0

अमेरिका बनेगा

ग्रेट या गट्टर

ई-पत्रिका

Let's
360°

Media Consultancy

Web solution

Advertising

Publication

Languages Services

Survey & Research

Branding

AV Production

Campaign management

Event organizer

PR partner, PR associate

Content writer & provider

Media analyst

URJAS MEDIA VENTURE IS PERHAPS THE ONLY CONSULTING FIRM THAT CAN GIVE YOUR ORGANISATION A 360 DEGREE MEDIA BUSINESS GROWTH CONSULTING THROUGH IT'S 360 CAPABILITIES. FOR US, CONSULTING DOES NOT ONLY MEAN MECHANICAL COST REDUCTION THROUGH BETTER IT APPLICATIONS, WE FIND OUT WHAT YOUR ORGANISATION REALLY NEEDS AND GIVE YOU AN INTELLECTUAL SOLUTION THAT HELP YOU REDUCE COST AS WELL AS HELPS YOURS BUSINESS GROW AND BEAT THE COMPETITION.

NOW!!
OUR CONSULTANT
WILL GET BACK
TO YOU IN 24
HOURS AND PUT
YOU IN TO THE HIGH
GROWTH PATH



BEAT THE COMPETITION
www.urjasmedia.com

SMS 'BUSINESS GROWTH'
TO +91-8826-24-5305 OR
E-MAIL info@urjasmedia.com



सकारात्मक भारत, सशक्त भारत

गुमनाम नायक

कोरल की पुकार, उमा का प्रयास



उमा मणि

उमा मणि की कहानी एक प्रेरणादायक सफर है। 49 वर्ष की उम्र में पहली बार स्कूबा डाइविंग करना, उनके जुनून और साहस को दर्शाता है। बचपन में कला के प्रति प्रेम को अनदेखा किया गया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शादी और परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद, 40 की उम्र में उन्होंने फिर से पेंटिंग शुरू की। जब उन्होंने कोरल रीफ को देखा, तो उनकी सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया। लेकिन, समुद्र में प्रदूषण देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने समुद्री जीवन को बचाने का फैसला किया।

उमा ने अपनी कला को एक हथियार बनाया और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। फिल्म 'कोरल वुमन' ने उनकी कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिली। आज, उमा एक प्रेरणा हैं, जो दिखाती हैं कि किसी भी उम्र में आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कला में बदलाव लाने की शक्ति होती है और अगर आपमें लगन हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है।

Cora!
Woman



राष्ट्रीय संपादक
संजय श्रीवास्तव

संपादकीय

संपादक
श्रीराजेश

प्रबंध संपादक
सच्चिदानंद पाण्डेय

राजनीतिक संपादक
अंशुमान त्रिपाठी

मेट्रो संपादक
शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव
डॉ. रुद्र नारायण

अंतर्राष्ट्रीय संपादक
श्रीश पाठक

कारपोरेट संपादक
गगन बत्रा

खेल संपादक
जलज श्रीवास्तव

डिजिटल संपादक
सुनीता त्रिपाठी

सहायक संपादक
संदीप कुमार

उप संपादक
मनोज कुमार
संतु दास

कला संपादक
जया वर्मा

वेब एवं आईटी विशेषज्ञ
अनुज कुमार सिंह

फोटो संपादक
विवेक पाण्डेय

विशेष संवाददाता
कमलेश झा
विकास गुप्ता

संवाददाता
संदीप सिंह
अनिरुद्ध यादव

ब्यूरो प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय)

अकुल बत्रा (अमेरिका)
सी.शिवरतन (नीदरलैंड)
जी. वर्मा (लंदन)
डॉ. मो. फहीम अकबर (पाकिस्तान)
ए. असगरजादेह (ईरान)
डॉ. निक सेरी (मलेशिया)

ब्यूरो प्रमुख (राष्ट्रीय)

आर. रंजन (नई दिल्ली)
संजय कुमार सिंह (लखनऊ)
कैप्टन सतीश सिन्हा (रांची)
निमेष शुक्ल (पटना)
नागेन्द्र सिंह (कोलकाता)
राकेश रंजन (गुवाहाटी)

विपणन

सत्यजीत चौधरी
महाप्रबंधक
ऑनलाइन प्रसार
सृजीत डे



DELENG19447

वर्ष: 8 अंक:2 फरवरी, 2025

Follow us:

Editorial/Business office

fb.com/cultcurrent

@Cult_Current

cultcurrent@gmail.com

URJAS MEDIA VENTURE

Head office: Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109, INDIA, Tel: +91 6289-26-2363

Corporate Office: 14601, Belaire Blvd, Houston, Texas 77083 USA Tel: +1 (832) 670-9074

Web: http://cultcurrent.in

Cult Current is a monthly e-magazine published by Urjas Media Ventures from Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109.

Editor: Srirajesh

Disclaimer: All editorial and non-editorial positions in the e-magazine are honorary. The publisher and editorial board are not obligated to agree with all the views expressed in the articles featured in this e-magazine. Cult Current upholds a commitment to supporting all religions, human rights, nationalist ideology, democracy, and moral values.

आवरण कथा

32



द्राम और कोलकाता

12

घड़कन व विरासत का अनमोल रिश्ता



16 अरविंद केजरीवाल 'सॉफ्ट हिंदुत्व' या नया पॉलिटिकल ड्रामा ?



26

अंतर्द्वंद में बांग्लादेश क्या अवामी लीग फिर से उठ खड़ी होगी?



2025 महाकुंभ 68 संस्कृति के संगम में अध्यात्म की दिव्यता

राजनीति का नया वाद: लोकवाद 22

लोक बनाम सत्ता: केन्या में लोकतंत्र की जगं 28

इजराइल: स्थायी जीत या अस्थायी राहत? 30

इसरो का स्पेडेक्स: इस कीर्तिमानी सफलता के मायने 74

'फायर गर्ल' माहिरा शर्मा की बोल्ट तस्वीर पर बोले फैस- 'बेबी डॉल, तुम कमाल कर रही हो!' 72



फिल्मी फसाना



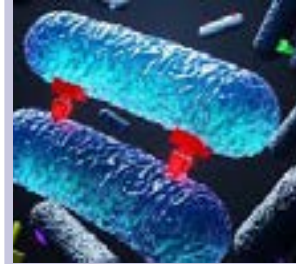
सामाजिक के भेदभाव से परेशान 'दंगल गर्ल'

एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा, जो अपनी अपकमिंग फिल्म मिसेज में एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करेंगी। समाज में मौजूद जेंडर इनइक्वलिटी पर अपने विचार शेयर किए। उनका मानना है कि समाज में महिलाओं से बहुत सी उम्मीदें की जाती हैं, जिनमें सबसे मेन ये है कि बच्चों को जन्म देने के बाद महिलाएं अपना करियर छोड़ देती हैं, लेकिन सिर्फ वो ही क्यों। सान्या का कहना है, 'ये स्वाभाविक बन चुका है कि महिलाएं बच्चे के बाद नौकरी छोड़ देती हैं, लेकिन बच्चा तो दोनों का है, है न? ये दोनों की जिम्मेदारी है। हमें एक अच्छा बैलेंस बनाने की जरूरत है।' सान्या मल्होत्रा ने अपनी फिल्मों 'जवान', 'दंगल', 'कथाल' और पगलेट में बहुमुखी भूमिकाएं निभाकर काफी पहचान बनाई है।

2025 में तहलका मचाने वाली खोजें

डीएनए विनिमय

नए शोध से पता चला है कि जीवाणु प्रजातियाँ बनाती हैं और डीएनए विनिमय (समजात पुनर्संयोजन) के माध्यम से एकजुटता बनाए रखती हैं। यह 'लैंगिक' प्रक्रिया अलग-अलग प्रजातियों की सीमाओं को मजबूत करती है, जो पहले की मान्यताओं को उलट देती है कि जीवाणु प्रजातियाँ नहीं बनाते। इस खोज का सूक्ष्म जीव विज्ञान, चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान पर बड़ा प्रभाव है।



मिले प्राचीन मेंटल द्वीप

नए शोध से पृथ्वी के मेंटल के भीतर दो महाद्वीप के आकार के 'द्वीप' का पता चला है। ये प्राचीन क्षेत्र, कम से कम आधा अरब वर्ष पुराने हैं, और अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक गर्म हैं। यह खोज तेजी से बहने वाले मेंटल के विचार को चुनौती देती है, जिससे पता चलता है कि प्रवाह पहले की तुलना में कम है। भूकंप के कंपन का उपयोग करके, भूकंपविज्ञानी इन छिपी हुई संरचनाओं को देखने में सक्षम हुए हैं।

आईएसएस कू का स्पेसवॉक

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने आगामी स्पेसवॉक की तैयारी और अंतरिक्ष बागवानी पर शोध किया। मिशन 72 के सात सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक्स रखरखाव और कार्गो पैकिंग पर भी काम किया। नासा की सुनी विलियम्स और बुच विल्मोर ने स्पेसवॉक गियर व्यवस्थित करने से पहले स्वास्थ्य जांच पूरी की। उनका 6.5 घंटे का स्पेसवॉक, पुराने हार्डवेयर को हटाने और रोगाणुओं की खोज के लिए जनवरी में किया गया।



मंगल अन्वेषण के लिए नासा ने उन्नत रोवर टायरों का किया परीक्षण



नासा ने मंगल के समान क्षेत्र में आकार स्मृति मिश्र धातु स्प्रिंग वाले उन्नत रोवर टायरों का परीक्षण किया। मंगल की सतह का केवल 1% पता लगाने के बावजूद, नासा भविष्य के मिशनों की तैयारी कर रहा है। मंगल की चुनौतीपूर्ण सतह के कारण टिकाऊ और लचीले टायर महत्वपूर्ण हैं। एसएमए स्प्रिंग टायर लाल ग्रह पर रोवर गतिशीलता के लिए एक आशाजनक समाधान हैं।

किआ सिरोस एसयूवी ने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश किया

किआ ने भारत के प्रतिस्पर्धी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नई सिरोस एसयूवी लॉन्च की है। हालांकि आधिकारिक मूल्य निर्धारण की घोषणा अभी बाकी है, पहली ड्राइव में इसके डिज़ाइन, इंजन प्रदर्शन, फीचर्स और आराम का पता चला। दक्षिण कोरियाई ऑटोमेकर का यह नया ऑफर मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसे स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। खरीदारों के लिए यह एक सार्थक विकल्प होगा या नहीं, यह देखना बाकी है।



नियुक्ति



एम. राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव को मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभागों का प्रभार सौंपा है। यह परिवर्तन डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल 15 जनवरी को समाप्त होने के बाद किया गया है।

इस्तीफा

नकुल जैन

सीईओ, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड



नकुल जैन ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वे सक्रिय रूप से नए सीईओ की तलाश में हैं और जल्द ही नई नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने अपना इस्तीफा 28 जनवरी, 2025 को दिया है।



उन्होंने कहा



तकनीकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत-अमेरिका के आपसी सहयोग और बढ़ाने की जरूरत है।

हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे।

श्रद्धांजलि



सरोजिनी नायडू

(13/02/1879-02/03/1949)

सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला नेता थीं, जिन्हें उनकी काव्य प्रतिभा के कारण 'भारत की नाइटिंगेल' कहा जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक विद्वान और वैज्ञानिक थे, जबकि उनकी माँ एक कवयित्री थीं। बचपन से ही वे मेधावी छात्रा थीं और कम उम्र में ही अंग्रेजी कविता लिखने लगी थीं। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई।

सरोजिनी नायडू का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था; वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से शामिल हुईं। वे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ीं। 1916 में वे महिलाओं की समानता और शिक्षा के लिए आंदोलन में शामिल हुईं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़-

चढ़कर भाग लिया और कई बार जेल भी गईं।

1925 में, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, जो उस समय महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। वे अपने प्रभावशाली भाषणों और तेजस्वी नेतृत्व के लिए जानी जाती थीं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिससे वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं। वे आजादी के बाद भी राष्ट्रीय एकता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों के लिए कार्यरत रहीं।

2 मार्च 1949 को लखनऊ में उनका निधन हो गया। उनकी कविताएँ और देशभक्ति की भावना आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वे न केवल एक कुशल कवयित्री थीं, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सशक्त नेता भी थीं, जिन्होंने भारत में महिलाओं की भूमिका को नई पहचान दी। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति, प्रकृति प्रेम और राष्ट्रीयता की झलक मिलती है। उनके योगदान को भारत हमेशा याद रखेगा।



DeepSeek ने मचाई हलचल: चीन का एआई चैटबॉट बना वैश्विक चर्चा का केंद्र

चीनी स्टार्टअप डीपसीक (DeepSeek) ने हाल ही में अपने एआई चैटबॉट की सफलता से वैश्विक तकनीकी जगत में हलचल मचा दी है। कंपनी ने कम लागत और कम संसाधनों का उपयोग करके एक प्रभावी एआई मॉडल विकसित किया है, जो प्रमुख अमेरिकी एआई मॉडलों को चुनौती दे रहा है। डीपसीक का चैटबॉट ऐपल ऐप स्टोर पर मुफ्त ऐप्स की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, जिससे अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। निविडिया के शेयरों में 17% तक की कमी देखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी तकनीकी उद्योग के लिए 'जागने की घंटी' करार दिया है। हालांकि, एलन मस्क सहित कुछ तकनीकी विशेषज्ञों ने डीपसीक के दावों पर संदेह व्यक्त किया है। डीपसीक ने हाल ही में साइबर हमले का सामना किया, जिसके बाद उसने नए उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है।

जर्मनी के चुनाव में करीब 1 करोड़ लोग नहीं दे पाएंगे वोट



जर्मनी में रहने वाले लगभग 1 करोड़ लोग, जो वयस्क आबादी का लगभग 14% हैं, जर्मन नागरिक नहीं होने के कारण आगामी संघीय चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। यह जर्मनी में रहने वाली अंतरराष्ट्रीय आबादी के लगभग 60% लोगों को बाहर कर देता है। कार्यकर्ता फिल बटलैंड, जो लंबे समय से निवासी हैं, इस मुद्दे को उजागर करते हैं, और बताते हैं कि जर्मनी में दशकों से रहने और काम करने के बावजूद, वह नागरिकता प्रतिबंधों के कारण भाग नहीं ले सकते हैं। उन्होंने नागरिकता प्राप्त करने के लिए सख्त आवश्यकताओं को भी इंगित किया है।

ग्रीनलैंड विवाद: डेनमार्क ने यूरोपीय समर्थन मांगा

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिक्सन ने बर्लिन, पेरिस और ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की, और राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों के खिलाफ समर्थन मांगा। ट्रंप ने रणनीतिक महत्व और प्राकृतिक संसाधनों का हवाला देते हुए आर्कटिक द्वीप को खरीदने में रुचि व्यक्त की, यहाँ तक कि सैन्य कार्रवाई का भी सुझाव दिया। फ्रेडेरिक्सन की यात्रा एक नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद यूरोपीय चिंता बढ़ने के बाद हुई। जर्मन चांसलर शोलज़ ने इस बात पर जोर दिया कि सीमाओं को बल से नहीं बदला जा सकता।



अफ्रीका में संघर्ष : गोमा में मानवीय संकट गहराया



पूर्वी कांगो के गोमा शहर में रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर में खरबों डॉलर की खनिज संपदा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एम23 लड़ाकों ने शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस कब्जे से संघर्ष और मानवीय संकट और बढ़ने की आशंका है। यह शहर पहले से ही अशांत है और इस कब्जे से हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं।

बाइडेन प्रशासन ने गाजा में कंडोम वितरण पर रवर्च के 4.3 करोड़ डॉलर



राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सभी अमेरिकी विदेशी सहायता पर रोक लगाने के फैसले की आलोचना हुई, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसका बचाव करते हुए बताया कि बाइडेन प्रशासन ने कंडोम वितरण कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ डॉलर आवंटित किए थे। लेविट ने कहा कि नवगठित सरकारी दक्षता विभाग और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने पाया कि गाजा में कंडोम के लिए करदाताओं के पैसे तय किए गए थे। उन्होंने इसे करदाताओं के पैसे की बेतुकी बर्बादी बताते हुए, जिम्मेदार खर्च पर ट्रंप के ध्यान पर जोर दिया। हमास के आतंकियों ने इजरायल में विस्फोटक लॉन्च करने के लिए कंडोम का इस्तेमाल किया।

बाइडेन ने रचि थी पुतिन की हत्या की साजिश!



रकर कार्लसन ने आरोप लगाया है कि बाइडेन प्रशासन ने पुतिन की हत्या की साजिश रची। फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर ने अपने पॉडकास्ट में दावा किया कि बाइडेन सरकार ने 'पुतिन को मारने की कोशिश की,' यह दावा उन्होंने बिना सबूत दिए पत्रकार मैट तैब्बी से दोहराया। क्रेमलिन ने जवाब में कहा है कि पुतिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने इन आरोपों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।



इटाली पीएम जियोर्जिया मेलोनी के खिलाफ जांच

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी पर लीबियाई पुलिस अधिकारी ओसामा अलमसरी नजीम को रिहा करने का आरोप है, जिन्हें आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया था। जांच के बावजूद मेलोनी को इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है, और इटली में जांच का सामना करना अपराध साबित नहीं करता है। मेलोनी ने कहा कि उन पर अपराध में सहायता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में जांच चल रही है। नजीम को उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही रिहा कर दिया गया और इटली के सरकारी विमान से घर भेज दिया गया। आईसीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है, और कहा है कि उन्हें उनकी रिहाई की जानकारी नहीं दी गई थी। मेलोनी का मानना है कि यह जांच एक वकील द्वारा शुरू की गई थी जिन्होंने नजीम की रिहाई और सरकारी विमान के उपयोग के बारे में शिकायत की थी। आईसीसी ने नजीम पर हत्या, यातना, बलात्कार और यौन हिंसा का आरोप लगाया था और इटली को यूरोप में उनके प्रवेश की सूचना दी थी।



सुपरसोनिक उड़ानें जल्द बनेंगी हकीकत



अमेरिका में दो विमानों के परीक्षण से सुपरसोनिक उड़ानें जल्द ही वास्तविकता बन सकती हैं। बूम सुपरसोनिक अपने XB-1 का प्रदर्शन करेगी, जबकि नासा X-59 का परीक्षण करेगी। सफल परीक्षणों से वाणिज्यिक सुपरसोनिक यात्रा शुरू हो सकती है, बूम के पास पहले से ही 130 से अधिक ऑर्डर हैं। XB-1 की उड़ान का लक्ष्य ध्वनि की गति को तोड़ना है, जो कॉनकोर्ड के बाद दशकों बाद वायु यात्रा में संभावित बदलाव का संकेत है।

क्या टाइम ट्रैवलर हैं एलन मस्क?

एलन मस्क ने टाइम ट्रैवलर होने के दावों को संबोधित किया है, जो 1953 की एक विज्ञान-कथा पुस्तक से प्रेरित हैं, जिसमें मंगल ग्रह पर 'एलन' नामक एक नेता की भविष्यवाणी की गई है। मस्क ने मजाक में ट्वीट किया कि वह 5000 साल पुराने एलियन टाइम ट्रैवलर हैं, और विडंबना यह है कि लोग उन पर विश्वास क्यों नहीं करते। वर्नर वॉन ब्रॉन की पुस्तक 'प्रोजेक्ट मास' में, मानवता को मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करते हुए और नेता का नाम 'एलन' बताया गया है। हालांकि यह एक संयोग है, लेकिन मूल जर्मन पांडुलिपि में भी मंगल के नेता का नाम 'एलन' है, जिससे रहस्य और गहरा हो गया है। मस्क, मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने के अपने लक्ष्यों के साथ, ऐसी अटकलों से अपरिचित नहीं हैं।



इसरो ने 100वें लॉन्च के साथ रचा इतिहास

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 29 जनवरी की सुबह 6:23 बजे एनवीएस-02 को ले जाने वाले अपने जीएसएलवी-एफ15 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह देश के अंतरिक्ष केंद्र से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। जीएसएलवी-एफ15 भारत के भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) की 17वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायो स्टेज के साथ 11वीं उड़ान है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ जीएसएलवी की 8वीं परिचालन उड़ान भी है। जीएसएलवी-एफ15 का पेलोड फेयरिंग 3.4 मीटर व्यास वाला एक धातु संस्करण है। इसरो के अनुसार, यह प्रक्षेपण एनवीएस-02 उपग्रह को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करेगा, जिससे भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली 4 से 5 उपग्रहों तक अपग्रेड हो जाएगी।

600 अस्पतालों ने 'आयुष्मान भारत' को कहा 'ना'



हरियाणा में लगभग 600 निजी अस्पतालों ने केंद्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये की बकाया राशि के कारण आयुष्मान भारत योजना की सेवाएं रोकने की धमकी दी है। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) का दावा है कि अगस्त 2024 से भुगतान लंबित है और चेतावनी दी है कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो अस्पताल 3 फरवरी से योजना के तहत इलाज बंद कर देंगे। यह ऐसे समय में आया है जब बीजेपी ने दिल्ली में निर्वाचित होने पर योजना को लागू करने का वादा किया है।

वैज्ञानिकों पर वैश्विक भरोसा अभी भी मजबूत

भारत सहित 68 देशों में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकांश लोग अभी भी वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हैं, भले ही सार्वजनिक विश्वास में गिरावट की चिंताएं हों। नेचर ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि लोगों का मानना है कि वैज्ञानिकों को समाज और नीति निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मिस्र के बाद भारत वैज्ञानिकों पर भरोसे के मामले में दूसरे स्थान पर है, जो विज्ञान में मजबूत विश्वास का संकेत देता है, हालांकि शिक्षा, आय और स्थान से प्रभावित है।



जैसलमेर में बर्ड फ्लू से 33 कुरजां की मौत



राजस्थान के जैसलमेर में बर्ड फ्लू से 33 कुरजां (डेमोइसेल क्रेन) की मौत हो गई है। 11 जनवरी से शुरू हुई मौतों में अधिकांश देगराय ओरन और मोहनगढ़ क्षेत्रों में हुई हैं। देगराय से लिए गए नमूनों में एच5एन1 एवियन फ्लू की पुष्टि हुई है, जबकि मोहनगढ़ में उड़ते हुए गिरे 14 क्रेन की जांच की जा रही है। स्थानीय पशु चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है।

पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का कम उपयोग करते हैं ग्रामीण किशोर



एएसईआर 2024 से पता चला है कि ग्रामीण भारत में 82.2% किशोर (14-16) स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह केवल 57% ने ही पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल किया। 76% ने सोशल मीडिया के लिए उपयोग किया। अधिकांश के पास पहुंच है, लेकिन कम के पास फोन हैं। लड़कों में स्मार्टफोन होने और लड़कियों की तुलना में अधिक डिजिटल कौशल दिखाने की संभावना है। केरल पढ़ाई से संबंधित स्मार्टफोन उपयोग में सबसे आगे है।

आंध्र में शुरू हो रहा व्हाट्सएप गवर्नेंस



आंध्र प्रदेश सरकार की 30 जनवरी से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू करने की योजना है। लोग अब मैसेजिंग एप के जरिए 161 सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों में बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नए प्रोग्राम का प्रदर्शन दिया। पहले चरण में सरकार 161 सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कैसे लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

प्राबोओ सुबिअन्तो ने कहा - मेरा डीएनए भारतीय

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोओ सुबिअन्तो की भारत यात्रा, जहां वह गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, समाप्त हो गई है, लेकिन यात्रा के दौरान उनकी टिप्पणियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सुबिअन्तो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लिया और इंडोनेशियाई सैन्य टुकड़ी से सलामी ली। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट का भी दौरा किया। हालांकि, उनकी सबसे चर्चित टिप्पणी राष्ट्रपति भवन में एक भोज के दौरान आई। भोजन से पहले, राष्ट्रपति सुबिअन्तो ने साझा किया कि उन्होंने आनुवंशिक अनुक्रमण और डीएनए परीक्षण करवाया था, जिससे उनके 'भारतीय डीएनए' का खुलासा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संगीत सुनते ही वह नाचने लगते हैं, जिसका कारण उनका भारतीय डीएनए है। इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जोर से हँसने लगे, जो उनके बगल में बैठे थे। इस कार्यक्रम का वीडियो राष्ट्रपति भवन ने यूट्यूब पर जारी किया।



भाजपा भारत की सबसे अमीर पार्टी



दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा, भारत की सबसे अमीर पार्टी भी है, जिसके पास कांग्रेस के 857 करोड़ की तुलना में 7,000 करोड़ से अधिक की नकदी और बैंक बैलेंस है। लोकसभा चुनाव 2023-24 में भाजपा का खर्च 1,700 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक है। कांग्रेस ने 600 करोड़ खर्च किए, जो तीन गुना वृद्धि है। भाजपा को दान में 1,685 करोड़ मिले, जो पिछले साल से दोगुना है।

भारत के 51 जिलों में भीषण बाढ़ और 91 जिलों में भीषण सूखा का खतरा

एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत में 51 जिले भीषण बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं, जबकि 118 जिलों में बाढ़ का खतरा अधिक है। वहीं, 91 जिले भीषण सूखे के खतरे से जूझ रहे हैं और 188 जिले सूखे के उच्च जोखिम में हैं। सीएसटीईपी और आईआईटी गुवाहाटी और मंडी द्वारा किए गए अध्ययन में विभिन्न राज्यों के 11 जिलों को बाढ़ और सूखे दोनों के प्रति उच्च संवेदनशीलता के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट जिलों की भेद्यता और इन आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान का आकलन करती है। यह बताती है कि सूखे का खतरा व्यापक है, जो 22 राज्यों के जिलों को प्रभावित करता है और यह खतरा तब और बढ़ जाता है जब जिले विभिन्न कारकों के कारण संवेदनशील होते हैं।





श्रीराजेश, संपादक

कूटनीति का युग

भारत की नई वैश्विक भूमिका

भारत के लिए यह स्थिति एक अवसर बन सकती है। एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में भारत इस युद्ध के समाधान में योगदान दे सकता है।

21 वीं सदी की वैश्विक राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां कूटनीति और शक्ति-संतुलन की कला में निपुणता ही किसी देश की स्थिरता और उसके वैश्विक प्रभाव का निर्धारण करती है। ऐसे समय में भारत के लिए यह एक अद्वितीय अवसर है कि वह अपनी भूमिका को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में सुदृढ़ कर सके। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के संभावित भारत दौरों ने इस संदर्भ में न केवल भारत की रणनीतिक स्थिति को उजागर किया है, बल्कि वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों को भी एक नई दिशा प्रदान की है।

रूस-यूक्रेन युद्ध, जो 2022 से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, अब एक ऐसे चरण में है जहां इसके समाधान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है। भारत ने इस संघर्ष में तटस्थता का रुख अपनाते हुए एक अनोखा संतुलन साधा है। जहां एक ओर भारत ने रूस से अपने पारंपरिक संबंध बनाए रखे हैं, वहीं दूसरी ओर उसने पश्चिमी देशों के साथ भी सकारात्मक संवाद की स्थिति बरकरार रखी है।

डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि सऊदी अरब इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है, एक नए दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। ट्रंप के अनुसार, तेल उत्पादन को बढ़ाकर रूस की आर्थिक शक्ति को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन यह दृष्टिकोण व्यावहारिकता से अधिक सैद्धांतिक है। रूस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ऊर्जा निर्यात पर आधारित है, और तेल की कीमतों में गिरावट से उसका राजस्व प्रभावित हो सकता है। लेकिन यह मानना कि केवल आर्थिक दबाव से रूस अपनी नीतियों में बदलाव करेगा, अतिसरलीकरण होगा।

भारत के लिए यह स्थिति एक अवसर बन सकती है। एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में भारत इस युद्ध के समाधान में योगदान दे सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की मेजबानी करने या संघर्ष-विराम वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव देना भारत के लिए एक सकारात्मक कूटनीतिक कदम हो सकता है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संभावित भारत दौरा भारत-रूस संबंधों को और गहराई प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐतिहासिक रूप से, भारत और रूस के संबंध रक्षा, ऊर्जा, और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में बेहद मजबूत रहे हैं। पुतिन की यात्रा के दौरान एस-400 मिसाइल प्रणाली जैसे रक्षा सौदों पर चर्चा होना तय है। साथ ही, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक के समुद्री मार्ग को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।

ऊर्जा संकट के इस दौर में रूस का महत्व भारत के लिए और भी बढ़ जाता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच, भारत के लिए रूस से आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही, पुतिन की यात्रा भारत को यह मौका दे सकती है कि वह रूस-यूक्रेन संघर्ष में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की संभावना को और मजबूत करे।

डोनाल्ड ट्रंप का संभावित भारत दौरा भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर प्रस्तुत करता है। ट्रंप प्रशासन के दौरान, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिली थी। उनकी इस यात्रा में क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की भूमिका पर चर्चा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इस समूह का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

ट्रंप की यात्रा भारत-अमेरिका के रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापारिक समझौतों को और प्रगाढ़ करने का एक मंच बन सकती है। भारत के लिए यह न केवल आर्थिक विकास का अवसर है, बल्कि अपनी सामरिक स्थिति को और मजबूत करने का भी अवसर है।

चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंधों के संदर्भ में भी यह दौरा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ बढ़ता सहयोग भारत को चीन के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। ट्रंप के दौरों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह हो सकता है कि यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ कर सके।

भारत के लिए यह स्थिति अवसरों और चुनौतियों दोनों का मिश्रण है। रूस और अमेरिका, दोनों के साथ संतुलन बनाए रखना भारतीय कूटनीति की परीक्षा लेगा। रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत को न केवल अपनी तटस्थता बनाए रखनी होगी, बल्कि अपने हितों को भी सुरक्षित करना होगा।

जहां एक ओर रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान में भारत की मध्यस्थता उसे वैश्विक राजनीति में एक प्रभावी शक्ति बना सकती है, वहीं दूसरी ओर, अमेरिका के साथ सहयोग उसे आर्थिक और सामरिक लाभ प्रदान कर सकता है। लेकिन इस सबके बीच, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव दिखाए बिना अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को कायम रखे।

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरों वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन दौरों के माध्यम से भारत यह प्रदर्शित कर सकता है कि वह न केवल एक विश्वसनीय साझेदार है, बल्कि एक जिम्मेदार और तटस्थ शक्ति भी है, जो वैश्विक संकटों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। भारत के पास इन दौरों के माध्यम से अपनी कूटनीतिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर है। चाहे वह रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की बात हो, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा हो, या चीन के साथ रणनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास हो – भारत के पास इन सभी मोर्चों पर नेतृत्व करने की क्षमता है।

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के संभावित भारत दौरों के माध्यम से, भारत को अपनी वैश्विक भूमिका को पुनः परिभाषित करने और अपनी कूटनीतिक शक्ति को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, यह यात्रा भारत के लिए केवल अवसर नहीं, बल्कि एक चुनौती भी होगी। वैश्विक दबावों और संघर्षों के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना, संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना, और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारियों को सुनिश्चित करना ही भारत की सफलता की कुंजी होगी। यह कूटनीति का युग है, और भारत इस बिसात पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह इन अवसरों का किस प्रकार उपयोग करता है और अपनी वैश्विक भूमिका को कितनी प्रभावी और स्थिरता के साथ स्थापित करता है।

Ajesh



srirajesh.journalist



@srirajesh



editor@cultcurrent.com



ट्राम और कोलकाता धड़कन व विरासत का अनमोल रिश्ता

कोलकाता—जिसे 'सिटी ऑफ जॉय' के नाम से जाना जाता है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पुराने समय की रौनक को आज भी सहेजे हुए है। इस शहर के विभिन्न पहलुओं में से एक सबसे खास और अनमोल कड़ी है—ट्राम। ट्राम और कोलकाता का रिश्ता सिर्फ यातायात का नहीं है, बल्कि यह शहर

की आत्मा का हिस्सा है। यह उस धड़कन का हिस्सा है, जो कोलकाता की सड़कों पर रोज धड़कती है, उसके बाशिंदों के जीवन से बंधी हुई है। ट्राम के बगैर कोलकाता की फिलहाल कोई कल्पना नहीं कर रहा। आज भी जिन सड़कों से ट्राम को बंद कर दिया गया है। उन सड़कों पर सूनी ट्राम की पटरियां हर कोलकातावासी को उलाहना देती हुई प्रतीत



होती है।

ट्राम का पहला परिचय कोलकाता को 1873 में हुआ था। तब यह घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी थी, जो सियालदह से आर्मेनियन घाट तक चलती थी। धीरे-धीरे समय बदला, और ट्राम भी इस बदलाव के साथ चलने लगीं। हालांकि, ट्राम अब घोड़ों द्वारा नहीं बल्कि बिजली से चलती हैं, लेकिन उनकी धीमी रफ्तार और पुराने अंदाज ने कोलकाता की विरासत को सजीव रखा है। यह न केवल कोलकाता के लोगों के लिए सस्ता परिवहन माध्यम है, बल्कि इसके चलते यह शहर अपने वायुमंडलीय प्रदूषण से भी बचा रहता है। यह कोलकाता के लोगों के जीवन में इस प्रकार घुलमिल गया है जैसे ट्राम के बगैर सवारी का कोई औचित्य ही नहीं। इसी तरह कोलकाता से हाथ रिक्रेश का भी संबंध रहा है, लेकिन यह मानव द्वारा खींचा जाना अमानवीय था। इसलिए यह बंद कर दिया गया लेकिन अब भी उसकी याद कोलकातावासियों के दिलों से महरूम नहीं हो सका है।

ट्राम:कोलकाता की पहचान

बंगाली और हिंदी सिनेमा ने ट्राम को एक नए आयाम में प्रस्तुत किया है। फिल्मों में अक्सर ट्राम को उन खास जगहों के रूप में दिखाया जाता है, जहां नायक अपनी नायिका से प्यार का इजहार करता है। इन दृश्यों ने ट्राम को सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं, बल्कि शहर की पहचान का प्रतीक बना दिया है। ट्राम की घंटियों की आवाज, उसके पहियों की सरसराहट, और उस पर सवार यात्रियों की बातें, सब मिलकर कोलकाता के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। स्कूल के दिनों में छूट वाली टिकट लेकर कोलकाता की सड़कों पर ट्राम से अवारगी करने का एक ऐसा अनुभव जिसे शायद शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। कोलकाता की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है 'अड्डा'। अच्छे रेस्तां और कॉफी हाउस के बावजूद कभी-कभी आप कुछ युवकों के समूह को बेवजह ही ट्राम में बैठकर गप्पे मारते, हंसी-ठिठोली करते आप अब देख सकते हैं।



इसी वजह से, ट्राम जीवन में रच-बस गया है। जब भी ट्राम से संबंधित कोई कानूनी मामला सामने आता है, तो यह केवल एक वाहन से जुड़ा मुद्दा नहीं होता, बल्कि यह कोलकाता की धरोहर, उसकी भावनाओं, और उसके अस्तित्व से जुड़ा होता है।

ट्राम पर छाप सियासी बादल

जनवरी 2023 में, कोलकाता उच्च न्यायालय की एक बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य शामिल थे, उन्होंने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका 'पीपल्स यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कोलकाता' (PUBLIC) नामक संगठन ने दायर की थी। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार की बिटुमिनाइजेशन प्रक्रिया (सड़क पर डामर बिछाने) के बाद ट्राम को हटा दिया जाएगा, और संभवतः उसके डिपो को निजी कंपनियों को बेच दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस निर्णय के पीछे कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था।

याचिका में कई उदाहरण दिए गए, जैसे लंदन, पेरिस, और इस्तांबुल



जैसे शहरों ने अपने ट्राम नेटवर्क को फिर से जीवंत किया है। ऐसे में, कोलकाता के ट्राम को हटाना न केवल अनैतिक है, बल्कि अव्यावहारिक भी। इसका प्रभाव न केवल शहर की आवाजाही पर पड़ेगा, बल्कि पर्यावरण, नागरिक स्वास्थ्य, और सामाजिक संरचना पर भी नकारात्मक असर डालेगा।

न्यायालय की चिंताएं और राज्य सरकार की जवाबदेही

मई 2023 में पहली सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को यह याद दिलाया कि सरकार कोलकाता में ट्राम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। इस पर अदालत ने भी आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि ट्राम जैसे धरोहर को समाप्त क्यों किया जा रहा है? 'यह एक धरोहर है, इसे क्यों समाप्त करना चाहते हैं? इसे क्यों नहीं सुधार सकते?' अदालत ने राज्य सरकार से पूछा।

राज्य सरकार ने कहा कि वे ट्राम को आधुनिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन न्यायालय का मानना था कि ट्राम को हटाने से पहले इसके प्रभावों पर एक विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि जब तक इस याचिका पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक ट्राम ट्रेक्स पर किसी भी तरह की बिटुमिनाइजेशन प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

ट्राम की विरासत और कोलकाता की संस्कृति

कोलकाता उच्च न्यायालय ने जून 2023 में एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, 'ट्राम कोलकाता की धरोहर का एक हिस्सा है, और राज्य सरकार का दायित्व है कि इस धरोहर को न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित किया जाए।' न्यायालय ने यह भी कहा कि जब कोलकाता के लोग यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को धरोहर का टैग मिलने पर गर्व करते हैं, तो उन्हें ट्राम सेवाओं के पुनरुद्धार पर भी गर्व होना चाहिए।

अदालत का यह वक्तव्य कोलकाता के लोगों की उन भावनाओं को सदा देता है, जो ट्राम के प्रति हैं। ट्राम केवल एक वाहन नहीं है, यह कोलकाता की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। इसके अस्तित्व को समाप्त करना न केवल एक परिवहन माध्यम को समाप्त करना होगा, बल्कि एक शहर की आत्मा को समाप्त करना होगा।

भविष्य की चुनौतियां और ट्राम का अस्तित्व

जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, कोलकाता की सड़कों पर ट्राम की आवाज धीरे-धीरे कम हो रही है। वर्तमान में, जहां ट्राम नेटवर्क का विस्तार 116.62 किलोमीटर तक था, अब केवल 33.04 किलोमीटर पर ही ट्राम चल रही हैं। कोलकाता का भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

लेकिन यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोलकाता की यह धरोहर संरक्षित रहे। राज्य सरकार और न्यायालय के बीच चल रही इस खींचतान का अंत क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी हो, कोलकाता के लोगों के दिल में ट्राम की जगह हमेशा रहेगी।

कोलकाता की धड़कन: ट्राम

शायद एक दिन कोलकाता की ट्राम फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ महानगर की सड़कों पर दौड़ती नजर आए, जैसे वह पुराने दिनों में दौड़ा करती थी। शायद कोलकाता के लोग फिर से ट्राम पर बैठकर अपने जीवन की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकें, और उन पलों को जी सकें, जो उन्हें इस शहर से जोड़ते हैं।

ट्राम और कोलकाता का यह रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे जितनी भी चुनौतियां आएँ, कोलकाता की आत्मा में ट्राम हमेशा जीवित रहेगी। यह महानगर और उसकी ट्रामें एक-दूसरे के साथ धड़कते रहेंगे, एक ऐसे धागे से बंधे जो समय के साथ कभी कमजोर नहीं होगा।





अरविंद केजरीवाल

'सॉफ्ट हिंदुत्व' या नया पॉलिटिकल ड्रामा ?

अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक मंचों पर रामायण और हनुमान चालीसा का उल्लेख कर विरोधियों पर निशाना साधने का तरीका अपनाया है। यह उनकी छवि से अलग है...

संतु दास

अरविंद केजरीवाल का उदय भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रूप में हुआ था, जहाँ उन्होंने अपने समर्थकों को यह भरोसा दिलाया कि वे धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति की स्थापना करेंगे। उनके शुरुआती कदमों से यह संदेश साफ़ था कि वह पारंपरिक राजनीति के विपरीत, एक ऐसी व्यवस्था

लाना चाहते थे जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो और जनसेवा पर आधारित हो। लेकिन हाल के वर्षों में, केजरीवाल की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है— जिसे विश्लेषक 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की राजनीति के रूप में परिभाषित करते हैं।

हाल ही के एक इंटरव्यू में, केजरीवाल ने स्वयं को हनुमान भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं। यह



पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं को सार्वजनिक रूप से साझा किया हो। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने से पहले भी, वे हनुमान मंदिर गए थे और मीडिया के कैमरों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। यह न सिर्फ़ धार्मिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि केजरीवाल की राजनीति अब हिंदू प्रतीकों के इर्द-गिर्द घूमने लगी है।

यह बदलाव केवल धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। केजरीवाल ने अपने राजनीतिक मंचों पर रामायण और हनुमान चालीसा का उल्लेख कर विरोधियों पर निशाना साधने का तरीका अपनाया है। यह एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि से अलग है, जो एक दशक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ़ खड़ा हुआ था, और जिसकी राजनीति धर्म और जाति से परे थी। इस परिवर्तन का कारण समझने के लिए, हमें पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीतिक रणनीति पर गौर करना होगा।

केजरीवाल के इस परिवर्तन का मुख्य कारण राजनीतिक लाभप्राप्ति है। जब 2017 के एमसीडी चुनाव में 'आप' को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, तब से केजरीवाल ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। एमसीडी की कुल 270 सीटों में से 'आप' ने मात्र 48 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 181 सीटों पर जीत दर्ज की। इस हार के बाद से केजरीवाल ने

जनता से जुड़ने और चुनावी गणित साधने के लिए धर्म और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया।

2018 में, दिल्ली की 'आप' सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत उन्हें अयोध्या, रामेश्वरम, वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाता है। इस कदम से 'आप' ने अपने लिए एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक वर्ग तैयार किया, जो विशेषकर हिंदू मतदाताओं को साधने के लिए था।

2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान, केजरीवाल ने नोटों पर हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर छापने की बात कही थी। यह सुझाव सीधा हिंदू भावनाओं को साधने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे के समानांतर एक 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की छवि प्रस्तुत की जा सके। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार रामराज्य के सिद्धांतों का पालन करती है, जो हिंदू धार्मिक और नैतिक आदर्शों से प्रेरित हैं।

केजरीवाल के इस धार्मिक झुकाव को कई विश्लेषक 'सॉफ्ट हिंदुत्व' का उदाहरण मानते हैं, जो भारतीय राजनीति में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। 2014 के बाद से, बीजेपी ने 'हिंदुत्व निहित राष्ट्रवाद' को बढ़ावा दिया, जिसने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को चुनौती दी। इसी के तहत कई राजनीतिक दलों ने यह महसूस किया कि केवल धर्मनिरपेक्ष राजनीति से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती।

2018 तक केजरीवाल धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हनुमान मंदिरों में जाने और हनुमान चालीसा का पाठ करने जैसी गतिविधियाँ इस बात का संकेत हैं कि अब केजरीवाल भी धर्म की राजनीति में उतर चुके हैं। यह बदलाव उनकी पार्टी की व्यापक स्वीकार्यता और चुनावी सफलताओं के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन यह उनके पुराने आदर्शों और भ्रष्टाचार विरोधी छवि से अलग है।

चुनावी रणनीति और भविष्य

'आप' ने हाल ही में पुजारी-ग्रंथी योजना की घोषणा की है, जिसमें मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को मासिक वेतन देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही, दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ़ कड़े कदम उठाने का निर्णय भी 'आप' की चुनावी रणनीति का हिस्सा है।

अरविंद केजरीवाल का यह राजनीतिक सफर इस बात का प्रमाण है कि भारतीय राजनीति में 'सॉफ्ट हिंदुत्व' का आकर्षण बढ़ रहा है। चुनावी सफलता और व्यापक जन समर्थन पाने के लिए धर्म का सहारा लेना अब सिर्फ़ बीजेपी तक सीमित नहीं रहा है।

दिल्ली की 7 विधानसभा सीटें, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक

केजरीवाल के इस धार्मिक झुकाव को कई विश्लेषक 'सॉफ्ट हिंदुत्व' का उदाहरण मानते हैं।



जब दिल्ली दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम समुदाय के दर्द को नहीं सुना, तब यह स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल अपने हिंदू वोट बैंक को खोना नहीं चाहते थे।

अरविंद केजरीवाल की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि वे धार्मिक प्रतीकों का सावधानीपूर्वक उपयोग कर रहे हैं, वे हिंदू और मुस्लिम दोनों को आकर्षित कर रहे हैं।



भूमिका निभाते हैं। इनमें सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, बल्लीमारान, मटिया महल और बाबरपुर सीटें प्रमुख हैं। लेकिन केवल मुस्लिम वोटों के सहारे चुनाव जीतने की असंभवता को समझते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब वह हिंदू मतदाताओं को भी साधने की कोशिश में हैं।

वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस का पतन और उसके वोट बैंक का आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होना इस बदलाव का मुख्य कारण है। कांग्रेस, जो पहले मुस्लिम मतदाताओं का प्रमुख आधार मानी जाती थी, अब आम आदमी पार्टी के आगे कमजोर हो गई है। केजरीवाल को विश्वास है कि मुस्लिम वोट उनके पास सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने हिंदू प्रतीकों का सहारा लेना शुरू किया है। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान मंदिर में माथा टेकना शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ये बदलाव उनकी 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की छवि को दर्शाता है, जो उन्हें बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व से अलग दिखाता है।

जब दिल्ली दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम समुदाय के दर्द को नहीं सुना, तब यह स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल अपने हिंदू वोट बैंक को खोना नहीं चाहते थे। शाहीन बाग में चल रहे धरनों से भी दूरी बनाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी छवि मुस्लिम समर्थक के रूप में न बने, ताकि वे हिंदू मतदाताओं को न खोएं।

दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल का यह रुख एक बड़ी रणनीति का

हिस्सा है। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय थे, लेकिन अब उन्होंने गोल टोपी की जगह हनुमान की गदा थाम ली है। इस बदलाव का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना है। चुनावी राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, और हनुमान का चयन करके केजरीवाल ने हिंदुत्व के साथ एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

बीजेपी ने भगवान राम को पहले ही अपने राजनीतिक केंद्र में रखा हुआ है, जबकि केजरीवाल ने हनुमान का चुनाव किया। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में हनुमान चालीसा का पाठ और प्रचार के दौरान हनुमान की गदा लेकर वोट मांगने की उनकी तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं। यह केवल प्रतीकों का चयन है, जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। केजरीवाल बीजेपी को जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वे हिंदुत्व के विमर्श का हिस्सा बन गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की भी चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी का रुख साफ है, वे मुस्लिम समुदाय को चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं करते। जबकि केजरीवाल मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से अलग, केजरीवाल एक 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की राह पर हैं, जो उन्हें मुस्लिम समुदाय से दूर नहीं होने देता।

अरविंद केजरीवाल का असली लक्ष्य हिंदू वोट है, लेकिन वे मुस्लिम

वोटों को छोड़ना भी नहीं चाहते। इस स्थिति में वे एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे दोनों समुदायों के बीच विश्वास को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं।

केजरीवाल एक धर्म विशेष के वोट पाने के लिए दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत का व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, यह संतुलन केजरीवाल नहीं बना रहे हैं, बल्कि परिस्थिति खुद इसे बना रही है।

आखिर में, दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की नीति और मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश को एक चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। वह अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा ले रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोटों को भी अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना है, और इस रणनीति ने उन्हें दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

इस चुनावी समीकरण में अरविंद केजरीवाल की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि वे धार्मिक प्रतीकों का सावधानीपूर्वक उपयोग कर रहे हैं, जिससे वे हिंदू और मुस्लिम दोनों मतदाताओं को आकर्षित करने में सक्षम हो रहे हैं। उनका यह संतुलन न केवल दिल्ली की राजनीति में बल्कि देश की व्यापक राजनीतिक स्थिति में भी एक नया आयाम जोड़ रहा है।



वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक नया युग शुरू होने वाला है, जहां क्वांटम टेलीपोर्टेशन और पारंपरिक नेटवर्क एक साथ काम कर सकते हैं। हाल ही में एक अभूतपूर्व प्रयोग ने यह साबित कर दिया है कि क्वांटम और पारंपरिक नेटवर्क एक ही ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संचालित हो सकते हैं। यह प्रयोग एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्वांटम नेटवर्क को बड़े पैमाने पर लागू करना आसान होगा।

जब हम बात करते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन की तो शायद सबसे पहले दिमाग में 'टेलीपोर्टेशन' शब्द आता है, जो हमें साइंस फिक्शन फिल्मों के पात्रों की याद दिलाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुँच जाते हैं। हालांकि, यहाँ मामला कुछ अलग है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब है, क्वांटम अवस्था को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना भौतिक रूप से भेजे पहुंचाना। यह क्वांटम एंटीगलमेंट के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें दो कणों की अवस्थाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। इस तकनीक का उपयोग भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, और अन्य महत्वपूर्ण नेटवर्किंग कार्यों में होगा। इस प्रयोग ने इस प्रक्रिया को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि अब यह प्रदर्शित किया गया है कि क्वांटम सिग्नल को एक ही फाइबर में पारंपरिक ऑप्टिकल ट्रैफिक के साथ भेजा जा सकता है।

प्रयोग की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

इस प्रयोग में, क्वांटम टेलीपोर्टेशन को 30.2 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पूरा किया गया, जिसमें पारंपरिक संचार ट्रैफिक भी चल रहा था। इस फाइबर में 400 गीगाबिट प्रति सेकंड की क्लासिकल ट्रैफिक यानी परंपरागत डेटा ट्रांसफर हो रहा था। क्वांटम अवस्था को सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया, और इसके लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक 'बेल स्टेट मापन' का उपयोग किया गया। इस प्रयोग की सबसे खास बात यह रही कि क्वांटम सिग्नल को इस तरह भेजा गया कि इसे उच्च शक्ति के क्लासिकल सिग्नल से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हम पौराणिक कथा 'समुद्र मंथन' का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें अमृत और विष दोनों साथ में थे, लेकिन दोनों को अलग-अलग प्रकार से संभाला गया। इसी प्रकार, इस प्रयोग में क्वांटम और पारंपरिक सिग्नल को एक साथ संभालने का तरीका खोजा गया।

क्वांटम नेटवर्क और पारंपरिक नेटवर्क का संगम

वर्तमान में, जो इंटरनेट नेटवर्क हम उपयोग करते हैं, वह ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित होता है। इसमें डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रकाश की तरंगों का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्वांटम नेटवर्क को सक्षम करने के लिए हमें ऐसे नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जिसमें क्वांटम सिग्नल को भी भेजा जा सके। अब तक इस तरह के नेटवर्क को अलग से तैयार करने की जरूरत थी, जिससे बहुत अधिक लागत आती थी। लेकिन इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि क्वांटम और पारंपरिक सिग्नल को एक ही ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भेजा जा सकता है, जिससे लागत और बुनियादी ढांचे को बड़ा लाभ मिलेगा। यह बिल्कुल वैसा है, जैसे एक सड़क पर साइकिल और तेज गति वाली कारें एक साथ चलें, लेकिन दोनों का सफर सुरक्षित हो। वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने

'स्पॉटेनियस रमन स्कैटरिंग' नामक एक चुनौती को हल किया, जो उच्च शक्ति वाले क्लासिकल सिग्नल से पैदा होती है और क्वांटम सिग्नल को नुकसान पहुंचा सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए विशेष ऑप्टिकल फिल्टर और समय के अनुसार सही समायोजन का उपयोग किया गया।

क्वांटम और क्लासिकल नेटवर्क के फायदे

इस सफल प्रयोग से कई नए दरवाजे खुलेंगे। सबसे पहले, यह क्वांटम नेटवर्क को वास्तविक जीवन में लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भविष्य में, हम क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे, जो वर्तमान कंप्यूटिंग तकनीक से कहीं अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली होंगी। यह तकनीक डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। सनातन पौराणिक कथाओं में, हम 'गुप्तज्ञान' का उल्लेख पाते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु ने देवताओं को अमरता का गुप्त ज्ञान दिया था। उसी तरह, क्वांटम नेटवर्क गुप्त रूप से सुरक्षित डेटा ट्रांसफर का भविष्य है। इसे सरल शब्दों में समझा जा सकता है कि जैसे अमृत को छिपाकर रखा गया था, ताकि कोई गलत हाथों में न जाए, वैसे ही क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डेटा को सुरक्षित रखेगी और उसे किसी भी प्रकार के साइबर हमले से बचाएगी।

भविष्य की चुनौतियाँ और संभावनाएँ

हालांकि इस प्रयोग ने काफी सफलता हासिल की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ सामने हैं। क्वांटम सिग्नल को बिना किसी विकृति के लंबे समय तक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, यह तकनीक वर्तमान में बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए महंगी हो सकती है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, तकनीक में और सुधार होगा, और इसकी लागत कम होगी। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि हर युग में एक नया अवतार आता है जो मानवता के लिए नई दिशा दिखाता है। उसी तरह, तकनीकी क्षेत्र में भी क्वांटम नेटवर्क एक नया अवतार है, जो भविष्य में हमारे जीवन को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

क्वांटम और पारंपरिक नेटवर्क का यह संगम एक विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रयोग हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहां क्वांटम नेटवर्क न केवल इंटरनेट की गति और क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि डेटा की सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा। जैसे महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाई थी, वैसे ही यह तकनीक हमारी डिजिटल दुनिया में नए प्रकार की सुरक्षा और तेज गति की रणनीति लेकर आएगी।

अभी यह शुरुआत है, और भविष्य में हम इस तकनीक के और भी अद्भुत और चौंकाने वाले परिणाम देखेंगे।

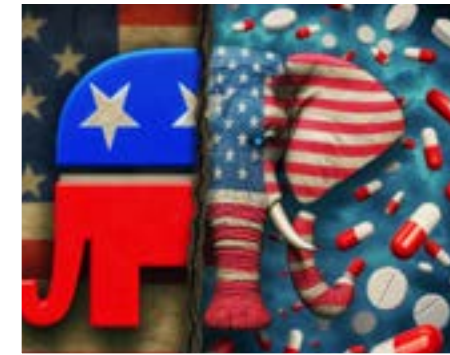
क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धि



राजनीति का नया 'वाद' लोकवाद



संदीप कुमार



जब वामपंथ, दक्षिणपंथ और मध्यमार्गी विचारधाराएं - विचारधाराओं की जटिलता से राजनीति को दिशा देते थे, लेकिन अब बीते दिनों की बात होने लगी है। ये वाद, जो कभी जनता की धड़कनों के साथ जुड़कर राजनीति के हर रंग को तय करते थे, अब हाशिए पर खड़े खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की जद्दोजहद में हैं। एक नई लहर, एक नए युग का आगमन हो चुका है 'पॉपुलिज्म' या लोकवाद।



सल 2025, हमने नई दहलीज पर कदम रखते ही हमें वैश्विक राजनीति में एक अनूठा और रोमांचक चलन उभरता दिखाई देने लगा है- 'पॉपुलिज्म' अर्थात लोकवाद। वर्तमान दौर की राजनीति अब न सिद्धांतों की बंधियों में बंधी है और न ही विचारधाराओं की कठोर सीमाओं में कैद। यह जनता की इच्छाओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी ताकत का प्रतिबिंब बनकर उभरी है। दुनिया का नया राजनीतिक युग अब लोकवाद के हाथों में है, और पुरानी विचारधाराएं उस पर असर डालने के लिए संघर्षरत हैं, जैसे एक गुजरा हुआ वक्त अपनी पहचान की तलाश कर रहा हो।



वह दौर था, जब वामपंथ, दक्षिणपंथ और मध्यमार्गी विचारधाराएं — विचारधाराओं की जटिलता से राजनीति को दिशा देते थे, लेकिन अब बीते दिनों की बात होने लगी है। ये वाद, जो कभी जनता की धड़कनों के साथ जुड़कर राजनीति के हर रंग को तय करते थे, अब हाशिए पर खड़े खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की जद्दोजहद में हैं। एक नई लहर, एक नए युग का आगमन हो चुका है—इसका नाम है 'पॉपुलिज्म' या लोकवाद। यह नया वाद न केवल तेजी से उभर रहा है, बल्कि राजनीतिक परंपराओं की दीवारों को तोड़ते हुए पुराने वादों को पीछे छोड़ता जा रहा है। आज की राजनीति एक ऐसी धारा की ओर मुड़ चुकी है जहाँ जनता का सीधा जुड़ाव और उनके सरोकार ही केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। पॉपुलिज्म ने राइट, लेफ्ट और सेंटर की जड़ों को हिला कर रख दिया है। चाहे भारत हो या अमेरिका और यूरोप के वे देश जहाँ जनता का असंतोष और आकांक्षाएँ नये नेतृत्व की इबारत लिख रही हैं—लोकवाद का परचम हर कोने में लहरा रहा है।



वर्तमान समय में पश्चिमी देशों में वामपंथ एक प्रकार से अस्तित्वहीन स्थिति में पहुंच चुका है। न केवल राजनीतिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी वामपंथ की पकड़ अत्यंत क्षीण हो चुकी है। यूरोप के अधिकांश हिस्सों में यह विचारधारा अपने प्रभाव खो चुकी है, और ब्रिटेन शायद इस प्रवृत्ति का एक अपवाद कहा जा सकता है। वहाँ प्रधानमंत्री केर स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन उसकी स्थिति भी लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। स्टार्मर,

जिन्हें एक पारंपरिक वामपंथी नेता के रूप में देखा जाता है, खुद को एलन मस्क जैसे धुर दक्षिणपंथी व्यक्तित्वों के बढ़ते प्रभाव से घिरा पाते हैं। मस्क, जो अपने नवाचारों और राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, लेबर पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, जबकि शेष यूरोप में वामपंथ की पहचान लगभग समाप्त हो चुकी है।

दूसरी ओर, दक्षिणपंथ भी अपनी पुरानी शक्ति और तेज खो चुका है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी, जो परंपरागत रूप से एक मजबूत दक्षिणपंथी आधार वाली पार्टी मानी जाती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक और विभाजनकारी नेतृत्व के कारण अंदरूनी संकट से जूझ रही है। ट्रंप की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) आंदोलन ने रिपब्लिकन पार्टी की पारंपरिक दक्षिणपंथी विचारधारा से पूरी तरह दूरी बना ली है। ट्रंप ने अपनी आलोचनात्मक और अपमानजनक रणनीति के तहत पार्टी के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया है, जिससे पार्टी के भीतर विभाजन गहरा हो गया है। निक्की हेली को उन्होंने 'बर्डब्रेन' कहकर अपमानित किया, तो जॉन बोल्टन को 'डंब ऐज अ रॉक' कहकर उनकी आलोचना की। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के पुराने स्तंभों, जैसे डिक चेनी और उनकी बेटी लिज चेनी, को भी अपने आक्रामक अभियान का हिस्सा बनाया है।

यह साफ तौर पर दर्शाता है कि ट्रंप का 'मागा' आंदोलन अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी की परंपरागत दक्षिणपंथी विचारधारा से बहुत दूर जा चुका है। यह एक नई विचारधारा के रूप में उभरा है, जो पारंपरिक दक्षिणपंथ से न केवल भिन्न है, बल्कि उसे चुनौती भी दे रहा है। इस प्रकार, वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ही पश्चिमी राजनीति में अपनी पुरानी पहचान खोते जा रहे हैं, और नए, उग्र विचारों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ चुकी है, जो राजनीति के बदलते परिदृश्य का प्रतिबिंब है।

वर्तमान समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक विचारधाराओं का परिदृश्य तीव्र गति से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ मतपेटियों और चुनाव परिणामों तक सीमित नहीं है,

बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। आर्थिक विश्लेषक रुचिर शर्मा ने हाल ही में अपने एक लेख में इस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया कि जिन विकासशील देशों में हाल के चुनाव हुए, वहां 85% सत्ताधारी दलों को हार का सामना करना पड़ा। यह आँकड़ा न केवल राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पारंपरिक राजनीतिक विचारधाराएं अब जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हो रही हैं। फ्रांस और इटली जैसे देशों में नई विचारधाराओं का उदय इस बदलाव का प्रतीक है, और जर्मनी भी जल्द ही इसी राह पर चल सकता है। स्पष्ट है कि पारंपरिक वामपंथ और दक्षिणपंथ अपने पुराने रूप में अब संघर्षरत हैं, और दुनिया तेजी से एक नई विचारधारा की ओर अग्रसर हो रही है।

इस नई विचारधारा का नाम है—लोकवाद (पॉपुलिज्म)। यह एक ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण है जो परंपरागत वाम, दक्षिण और मध्यमार्गी विचारधाराओं को चुनौती दे रहा है। इस आंदोलन के सफलतम प्रतीकों में डोनाल्ड ट्रंप, जियोर्जिया मेलोनी, विक्टर ओर्बन और मरीन ली पेन जैसे नेता शामिल हैं। इन नेताओं की नीतियां और रणनीतियां पारंपरिक दक्षिणपंथ से भिन्न हैं, और इन्हें दक्षिणपंथी करार देना एक सरलीकृत दृष्टिकोण होगा। पॉपुलिज्म का उदय इस बात का प्रमाण है कि जनता अब जटिल विचारधाराओं और भारी-भरकम सिद्धांतों से ऊब चुकी है और उसे सरल, प्रत्यक्ष और व्यावहारिक नीतियों की ओर आकर्षण हो रहा है।

लोकवाद और इसकी परिभाषा पॉपुलिज्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता और व्यावहारिकता में निहित है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो जटिल नैतिकता, इतिहास की गहराई या तथ्यों की पेचीदगियों में उलझने के बजाय सीधी और सरल राजनीति की बात करती है। यह लोगों के दैनिक जीवन के मुद्दों को प्राथमिकता देती है और इसीलिए इसकी अपील व्यापक और प्रभावशाली है। पॉपुलिज्म का यह रूप अब दुनिया के विभिन्न देशों में उभर रहा है, और भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ संस्कृति का उल्लेख करते हुए इसकी की थी, जिसमें वोट पाने के लिए मुफ्त और सेवाएं देने का प्रलोभन दिया जाता

इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया था। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा ने भी इस लोकवादी राजनीति का सहारा लिया और मुफ्त बिजली, पानी और अन्य लाभों की पेशकश की। यह एक स्पष्ट संकेत है कि पॉपुलिज्म की राजनीति अब मुख्यधारा का हिस्सा बन चुकी है, और यह न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक धारा के रूप में उभर रही है।

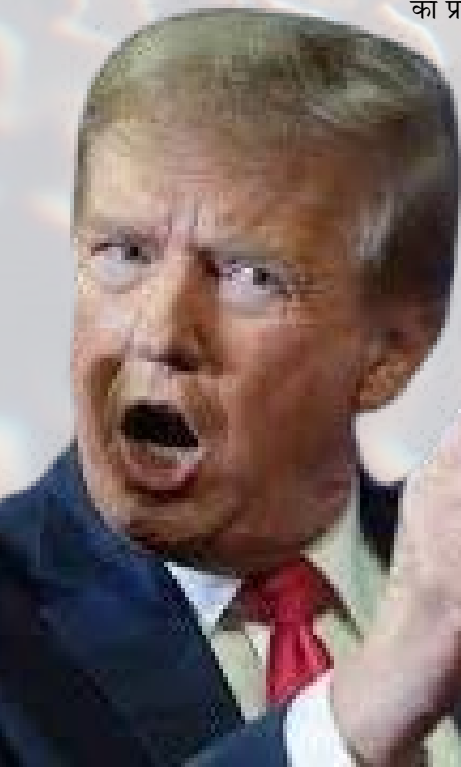
पॉपुलिज्म का यह उदय उन देशों और नेताओं की ओर इशारा करता है, जो तेजी से बदलती दुनिया में लोगों की आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पुरानी विचारधाराएँ और 'इज्ज' जटिलता में उलझे हैं, वहीं पॉपुलिज्म साधारण, प्रत्यक्ष और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित राजनीति का पक्षधर है। यही कारण है कि यह आंदोलन आज के समय में राजनीतिक परिदृश्य पर गहराई से अपनी जड़ें जमा रहा है।

भारत में पॉपुलिज्म की राजनीति तेजी से उभर रही है और इसने परंपरागत वामपंथ, दक्षिणपंथ, और मध्यमार्गी विचारधाराओं को पीछे छोड़ दिया है। आज की राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धताएं कमजोर पड़ रही हैं, और आम आदमी पार्टी (आप) जैसी पार्टियों ने खुद को इस बदलाव के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। ये पार्टियां विचारधारा से अधिक लोकलुभावन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो सीधे जनता की समस्याओं से जुड़ी होती हैं। मुफ्त सुविधाओं का वादा, व्यक्तिगत लाभों की पेशकश, और जन-समर्थक नीतियों का प्रचार वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का प्रमुख स्वरूप बन गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी अब इसी राह पर चल रही है। पहले हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद को अपनी पहचान बनाने वाली भाजपा अब पॉपुलिज्म की राजनीति में विश्वास करती दिख रही है। 'रेवडी संस्कृति' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के बावजूद, हालिया चुनावों में भाजपा ने भी मुफ्त सुविधाओं और लोकलुभावन घोषणाओं को अपनी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विचारधारा-रहित राजनीति ने सभी प्रमुख दलों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और पॉपुलिज्म का प्रभाव अब भारत की राजनीति में गहराई से समाहित हो गया है। पॉपुलिज्म का स्वरूप हर देश में भिन्न-भिन्न होता है, और इसका उद्देश्य जनता की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूरा करना है। पॉपुलिज्म विकसित देशों में

अक्सर प्रवासियों के निष्कासन, विदेशी संस्कृतियों के प्रति आशंका, और राष्ट्रवादी नीतियों के रूप में प्रकट होता है। डोनाल्ड ट्रंप, विक्टर ओर्बन, और जियोर्जिया मेलोनी जैसे नेता अपने-अपने देशों में राष्ट्रवाद और लोकलुभावन नीतियों के प्रतीक बन चुके हैं, जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती हैं। दूसरी ओर, भारत जैसे विकासशील देशों में पॉपुलिज्म का रूप थोड़ा अलग है। यहाँ पॉपुलिज्म सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, मुफ्त सुविधाओं, और सीधे जनता से जुड़े मुद्दों के रूप में प्रकट होता है। भारत में लोकलुभावन राजनीति के कई उदाहरण मिलते हैं, जहाँ मुफ्त बिजली, पानी, राशन और अन्य सुविधाओं का वादा आम चुनावी घोषणाओं का हिस्सा बन गया है। पॉपुलिज्म के अंतर्गत ऐसी नीतियां न केवल गरीब और मध्यम वर्ग को लक्ष्य बनाती हैं, बल्कि समाज के सभी वर्गों में लोकप्रियता हासिल करती हैं।

पॉपुलिज्म का उदय इस बात का संकेत है कि पुरानी विचारधाराएँ—वामपंथ, दक्षिणपंथ, और मध्यमार्गी—अब अपना प्रभाव खो चुकी हैं। ये विचारधाराएँ अब जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो रही हैं। पॉपुलिज्म इन पुरानी सीमाओं से मुक्त होकर जनता की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान देना होता है। यही कारण है कि पॉपुलिज्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और परंपरागत 'इज्मों' को पीछे छोड़ रहा है। वर्तमान समय में विचारधारा आधारित राजनीति अब हाशिए पर जा रही है। पॉपुलिज्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी विशिष्ट वैचारिक ढांचे में बंधा नहीं है। यह किसी भी पक्ष की विचारधारा को अपनाने की बजाय, जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम है।

दुनिया की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है, जिसमें पॉपुलिज्म मुख्य धारा के रूप में उभर रहा है। परंपरागत वामपंथ, दक्षिणपंथ और मध्यमार्गी विचारधाराएँ अब संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि वे आधुनिक मतदाताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। लोकवाद की राजनीति, जो जनता के दिल और दिमाग में सीधे तौर पर अपील करती है, अब वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व कायम कर रही है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप—पॉपुलिज्म का प्रभाव अब हर जगह महसूस किया जा रहा है। यह राजनीति के एक ऐसे युग की शुरुआत है जहाँ मतदाताओं की अपेक्षाएँ और विचारधाराओं पर हावी हो चुकी हैं।





नागेन्द्र सिंह

16 जुलाई, 2024 की दोपहर को जब बांग्लादेश के रंगपुर जिले में छात्र नेता अबू सईद को पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं ढाका में एक बिल्कुल अलग दृश्य सामने आ रहा था। मछली पालन और पशुपालन मंत्रालय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के वरिष्ठ नेता और मंत्री अब्दुर रहमान अपने कार्यालय में आराम से एक स्थानीय कवि द्वारा कविता पाठ का आनंद ले रहे थे। एक वीडियो में वह कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे, अपनी दाहिनी गाल पर हाथ रखे, और कविता सुनने का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे ही उन्हें सईद की हत्या और बढ़ते हुए प्रदर्शनों के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने यह कहते हुए उसे नकारा कर दिया, 'कुछ नहीं होगा, नेता [हसीना] सब संभाल लेंगी।'

यह दृश्य, जिसमें एक ओर बांग्लादेश की सड़कों पर खून-खराबा हो रहा था और

इस हद तक हताश हो गए हैं कि वे अब राजनीति से बाहर जाने का सोच रहे हैं।

एक वरिष्ठ छात्र नेता ने इस बारे में अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, 'जब हमने हसीना सरकार को गिराने की योजना बनाई,

तो हमें लगा था कि हमारे नेता हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ी, तो हमारे नेता हमें छोड़कर भाग गए।' बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ता अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं।

अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अब तक पार्टी के किसी भी कृत्य पर कोई खेद या माफी नहीं आई है। बजाय इसके, पार्टी के प्रवक्ताओं ने छात्र आंदोलन को आतंकवादी

अंतर्द्वंद्व में बांग्लादेश

क्या अवामी लीग फिर से उठ खड़ी होगी?

दूसरी ओर एक मंत्री अपनी सुरक्षित स्थिति में शांति से बैठा था, देश के नागरिकों के लिए एक गहरे अंतर्द्वंद्व का प्रतीक बन गया। यह इस बात को उजागर करता है कि अवामी लीग का शीर्ष नेतृत्व जनता के बीच उठ रही समस्याओं और असंतोष से कितना disconnected हो चुका था।

महज तीन सप्ताह बाद, शेख हसीना सरकार को छात्र नेतृत्व वाले एक उग्र आंदोलन ने उखाड़ फेंका। 1 जुलाई से शुरू हुए प्रदर्शनों में 834 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20,000 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हसीना सरकार के खिलाफ यह आंदोलन इतना विशाल बन गया कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को भारत की ओर पलायन करना पड़ा। इस घटना ने 16 वर्षों से चल रही उनकी सत्ता का अंत कर दिया।

अब, पांच महीने बाद, अवामी लीग के लिए स्थिति उतनी ही कठिन हो चुकी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय इन घटनाओं को विदेशी साजिश का हिस्सा बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। पार्टी के महासचिव एएफएम बहाउद्दीन नसिम ने इस आंदोलन के लिए आरोप लगाते हुए कहा, 'हम एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार हुए हैं, जल्द ही इसका प्रमाण मिलेगा।' इस बयान ने पार्टी के नेताओं की असंवेदनशीलता और जनता से पूरी तरह से कट जाने को स्पष्ट किया।

अवामी लीग के भीतर इस समय गहरी अंतर्विरोधों की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एक ओर जहां शीर्ष नेताओं का दावा है कि उन्होंने सही दिशा में काम किया था, वहीं दूसरी ओर पार्टी के मध्य-स्तरीय नेता और कार्यकर्ता इस बात से निराश हैं कि पार्टी का नेतृत्व अब जनता से पूरी तरह से कट चुका है। बहुत से कार्यकर्ता

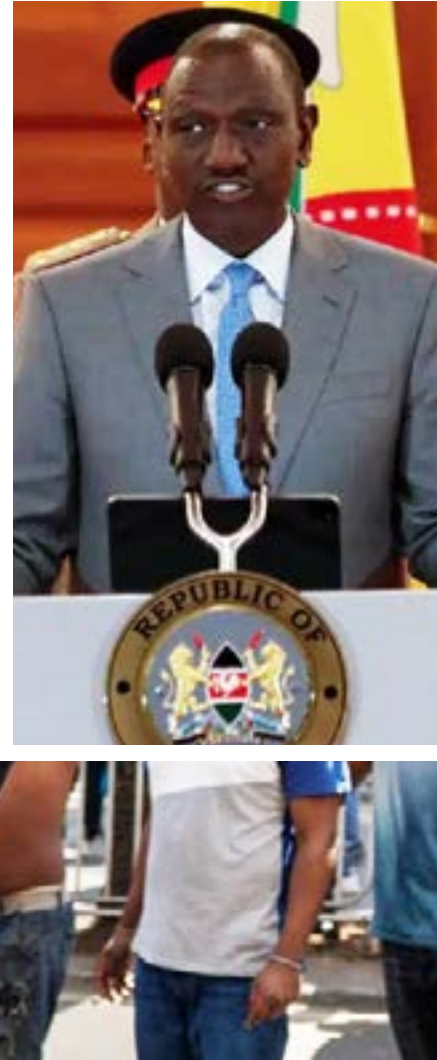
गतिविधि करार दिया और इसे पाकिस्तान समर्थक ताकतों का हिस्सा बताया। पार्टी के नेताओं का यह बयान केवल जनता की नाराजगी को और बढ़ा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार की रणनीतियों से पार्टी अपनी छवि सुधारने में नाकाम रही है।

अवामी लीग के पास अब खुद को पुनः स्थापित करने का एक कठिन रास्ता बचा है। पार्टी को अपनी पुरानी पहचान को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस प्रयास में सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के भीतर से आने वाली आलोचनाओं का सामना करना और जनता के बीच विश्वास बहाल करना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय करती है और सही दिशा में कदम उठाती है, तो वह अपने खोए हुए जनाधार को फिर से पा सकती है।

राजनीतिक विश्लेषक अली रियाज के अनुसार, 'अवामी लीग को अपनी गलतियों का माफी मांगने और पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को बदलाव की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। अगर ये शर्तें पूरी की जाती हैं, तो ही पार्टी का भविष्य सुरक्षित हो सकता है।'

अवामी लीग के लिए पुनर्निर्माण का रास्ता मुश्किल है, लेकिन यह असंभव नहीं है। पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा और जनता के बीच खोई हुई विश्वासनीयता को फिर से स्थापित करना होगा। यदि पार्टी अपने नेतृत्व और संरचना में सुधार करती है, तो शायद वह अगले चुनावों में हिस्सा लेने के लिए एक मजबूत स्थिति में आ सकती है। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि पार्टी किस हद तक अपने पिछले कार्यों पर आत्म-विश्लेषण और सुधार करेगी।

राष्ट्रपति रुटो की रणनीति यह दर्शाती है कि वे सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने लोगों को डराने और विभाजित करने के पुराने तरीकों का सहारा लिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे इस समय की युवा जनसंख्या की मांगों को कब तक अनदेखा कर सकेंगे।



लोक बनाम सत्ता

कल्ट करंट ब्यूरो

केन्या में लोकतंत्र की जंग

केन्या में हाल के दिनों में राजनीतिक स्थिति ने एक चिंताजनक मोड़ लिया है। जब 2024 के जनरल जेड विरोध प्रदर्शन हुए, तब राष्ट्रपति विलियम रुटो के पास दो स्पष्ट विकल्प थे: वह या तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर कदम उठाते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते, या फिर पुराने काले दौर की तरह सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा और दमन का सहारा लेते। दुर्भाग्य से, रुटो ने दूसरा रास्ता चुना और केन्या एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा और दमन के दौर में प्रवेश कर चुका है।

दमन और गायब हो रही आवाज़ें

पिछले कुछ महीनों में केन्या में बड़ी संख्या में लोगों का अचानक गायब होना चिंता का विषय बन चुका है। ये अपहरण बिना किसी कानून या प्रक्रिया का पालन किए हो रहे हैं, और इसके पीछे सरकार का हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रुटो सरकार, जो इन अपहरणों की जिम्मेदार मानी जा रही है, खुद इसकी जांच के आदेश देती रही है। यह एक प्रकार की ऑरवेलियन धोखाधड़ी है, जिसमें जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसे अनदेखा कर दें, जबकि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती रहती है। राष्ट्रपति के नजदीकी लोगों पर भी इस दमन का असर दिखा है। उदाहरण के लिए, जब केन्या के अटॉर्नी जनरल जस्टिन मुतुरी के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तब मुतुरी ने सीधे राष्ट्रपति से संपर्क किया, और उनके बेटे को तत्काल रिहा कर दिया गया। इस मामले में बोलने के कारण मुतुरी को रुटो के सहयोगियों से बार-बार आलोचना का सामना करना पड़ा। यह दर्शाता है कि सरकार का यह रवैया न केवल सामान्य नागरिकों के खिलाफ है, बल्कि सत्ता के नजदीकी लोग भी इससे अछूते नहीं हैं।

धोखे की राजनीति और लोकतांत्रिक दिखावा

राष्ट्रपति रुटो की सरकार, एक तरफ लोकतांत्रिक आदर्शों की बात करती है, तो दूसरी ओर अपने विरोधियों को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेती है। यह एक दोहरी राजनीति है, जहां रुटो ने तुर्की, युगांडा और रवांडा जैसे तानाशाही सरकारों से सहयोग बढ़ाया है और देश में विदेशी असंतुष्टों को गिरफ्तार कर या उन्हें निर्वासित करके अपनी सत्ता को और मजबूत किया है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने लोकतांत्रिक छवि को बनाए रखने के लिए रुटो, राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं।

एक बड़े सवाल का सामना केन्या के लोग कर रहे हैं: जब राजनीतिक नेतृत्व खुले तौर पर सच्चाई को विकृत करने का प्रयास

करता है, तब समाज कैसे प्रतिक्रिया करता है? राष्ट्रपति रुटो के इस रवैये ने न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान किया है, बल्कि लोगों में यह सवाल उठाया है कि क्या सरकार के खिलाफ विरोध करने का कोई अर्थ रह गया है? यह एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करता है जो अपने राजनीतिक वर्ग से विश्वास खो चुका है, लेकिन अपनी ताकत और बदलाव की क्षमता पर अब भी विश्वास करता है।

सच्चाई और विभाजन की राजनीति

केन्या के कैथोलिक बिशप सम्मेलन ने इस स्थिति को 'झूठ की संस्कृति' कहा है। उनका कहना है कि सरकार सच को अपने हिसाब से परिभाषित कर रही है, और सत्य केवल वही है जो सरकार कह रही है। यह एक गंभीर राजनीतिक समस्या है, जिसे न केवल केन्या में बल्कि दुनिया भर में उन देशों में देखा जा सकता है, जहां लोकतंत्र संकट में है। यह सवाल उठता है कि केन्या जैसी जगह में, जहां लोग परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं, वहां सरकार के झूठों और हिंसा से कैसे निपटा जाएगा?

राष्ट्रपति रुटो की यह रणनीति यह दर्शाती है कि वे सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने लोगों को डराने और विभाजित करने के पुराने तरीकों का सहारा लिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे इस समय की युवा जनसंख्या की मांगों को कब तक अनदेखा कर सकेंगे। जिस प्रकार से सरकार विरोध को दबा रही है, वह एक खतरनाक संकेत है कि केन्या की राजनीति में और अधिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है।

भविष्य का संघर्ष और लोकतंत्र का भविष्य

राष्ट्रपति रुटो के नेतृत्व में केन्या का भविष्य अस्थिर दिख रहा है। सत्ता के लिए यह संघर्ष केवल केन्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के उन अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए भी एक चेतावनी है, जहां सत्ता के भूखे नेता जनता की इच्छाओं और अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं। केन्या का यह राजनीतिक परिदृश्य न केवल देश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि यह संकेत है कि वैश्विक लोकतंत्र भी ऐसे ही खतरों का सामना कर रहा है।

केन्या के लोगों के लिए अब सवाल यह है कि क्या वे इस राजनीतिक धोखाधड़ी को सहन करेंगे, या फिर वे बदलाव की अपनी इच्छाओं को फिर से केंद्र में लाकर सरकार को जवाबदेह बनाएंगे।

यह आलेख सीएफआर के ब्लॉग पर प्रकाशित मिशेल गेविन के आलेख 'अकाउंटैबिलिटी गॉन मिसिंग इन केन्या' पर आधारित है।



इज़राइल स्थायी जीत या अस्थायी राहत?

ए. असगरजादेह

साल 2023 में 7 अक्टूबर को इज़राइल और हमास के बीच युद्ध ने न केवल पश्चिम एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया, बल्कि पूरे विश्व को शांति और सुरक्षा के संदर्भ में चिंतित कर दिया। इस युद्ध ने 15 महीनों के बाद कुछ शांतिपूर्ण समझौतों के साथ समाप्ति की ओर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इसके परिणामों को समझना अभी भी मुश्किल है। क्या इज़राइल ने वास्तव में अपनी सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया, या यह केवल एक अस्थायी सफलता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

विजय की परिभाषा और इज़राइल का उद्देश्य:

विजय की परिभाषा केवल सैन्य सफलता तक सीमित नहीं होती; इसमें रणनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति, क्षेत्रीय स्थिरता, और लंबे समय तक शांति की उम्मीदें भी शामिल होती हैं। इज़राइल ने 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसका उद्देश्य 'हमास को

नष्ट करना' है, जो एक आतंकवादी संगठन के रूप में ग़ज़ा पट्टी में शासन कर रहा था। हालांकि, इज़राइल की सेना ने हमास के उच्चतम नेताओं को मार डाला और उनके सैन्य ढांचे को तबाह कर दिया, लेकिन इस संगठन की ताकत और जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह फिर से उभर आया।

हमास के सदस्य अपनी रणनीति में लचीले हैं, और उन्होंने भारी नुकसान के बावजूद अपना नेटवर्क जारी रखा है। इज़राइल की सैन्य रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 17,000 हमास के सैन्य सदस्यों को मारा गया, लेकिन फिर भी संगठन अपनी ताकत बनाए हुए है, जिसका संकेत यह है कि पूरी तरह से हमास को नष्ट करना संभव नहीं था। युद्ध के बाद भी हमास के कई कार्यकर्ता ग़ज़ा में मौजूद हैं और इसकी जड़ें फिलिस्तीनी समाज में गहरी बसी हुई हैं।

इज़राइल की राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में सफलता:

इज़राइल का युद्ध में उद्देश्य सिर्फ हमास को नष्ट करना नहीं था, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। प्रधानमंत्री

बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीत के रूप में देखा और घोषणा की कि 'हमारी सेनाओं ने हमास को नष्ट कर दिया है और हमारे सभी युद्ध उद्देश्य पूरे हो गए हैं।' नेतन्याहू का यह बयान इस विचार को समर्थित करता है कि इज़राइल ने अपनी सैन्य ताकत का प्रभावी रूप से प्रदर्शन किया और अपनी सीमा के भीतर आने वाले खतरे को कम करने में सफलता प्राप्त की।

युद्ध के दौरान इज़राइल की सेनाओं ने कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिनमें हथियार भंडारण, रॉकेट लॉन्गिंग पैड, और अन्य रणनीतिक स्थल शामिल थे। इसके बावजूद, इज़राइल के पास यह सुनिश्चित करने की कोई योजना नहीं थी कि ग़ज़ा में स्थायी शांति स्थापित हो, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सैन्य कार्रवाई के परिणाम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं हो सकते। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि इज़राइल ने युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ग़ज़ा के नागरिकों की भारी संख्या में हुई हानि ने मानवाधिकारों और युद्ध अपराधों के सवाल को जन्म दिया।

ग़ज़ा का संकट और मानवीय दृष्टिकोण:

ग़ज़ा में युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ मानवीय संकट इज़राइल की सैन्य सफलता को सवालों के घेरे में डालता है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल हुआ। ग़ज़ा में लगभग 92% लोग विस्थापित हो गए, जिससे यह क्षेत्र भयंकर मानवीय संकट का

सामना कर रहा है। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के बीच नागरिक हत्याएं, शरणार्थी संकट, और खाद्य सुरक्षा जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

वर्तमान समय में, ग़ज़ा की हालत ऐसी है कि यहां के नागरिकों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अस्पतालों, स्कूलों और जल आपूर्ति प्रणाली का ढांचा टूट चुका है, जिससे ग़ज़ा में जीवन जीने की स्थिति और भी जटिल हो गई है। इज़राइल की सरकार ने यह दावा किया कि उसने नागरिकों के खिलाफ हिंसा को न्यूनतम किया, लेकिन युद्ध की हिंसा की वास्तविकता से इनकार करना असंभव है।

इरान और क्षेत्रीय शक्ति समीकरण:

इज़राइल के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है। इज़राइल और उसके सहयोगी देशों ने युद्ध के दौरान इरान के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश की। इज़राइल ने लेबनान में हिज़बुल्लाह और सीरिया में ईरानी सेना के ठिकानों पर हमले किए, जिससे इरान की सैन्य स्थिति में भी कुछ गिरावट आई। इसके अलावा, इज़राइल ने इरान के मिसाइल और रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया, जो एक बड़ी रणनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा सकता है।



चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कहा था, 'आप जानते हैं, 1890 के दशक में हमारा देश ... शायद सबसे समृद्ध था, क्योंकि यहां टैरिफ की कड़ी प्रणाली थी। 'और हमारे एक राष्ट्रपति थे - आप मैक्कनले को जानते हैं, है न? वह वास्तव में एक बहुत कुशल व्यवसायी थे, और उन्होंने उस समय देश के लिये अरबों डॉलर अर्जित किए थे।' ट्रंप की मंशा है अमेरिका को एक बार फिर महान बनाने की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'। जहां अधिकतर का मानना है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक बार फिर पुराने गौरव को पा लेगा, उसकी हेजीमॉनी वर्तमान से ज्यादा ताकतवर होगी तो कुछ विरोधाभास भी है, बहुतों का कहना है कि अमेरिका के लिए ट्रंप की योजना पुरानी शैली की मनमानी, अहंकारी, अदूरदर्शी अर्थव्यवस्था, अलगाववाद और श्वेत पुरुष वर्चस्व के इर्द-गिर्द केंद्रित है – उनकी नीतियां अमेरिका को दुनिया के सामने एक खलानायक और आर्थिक तौर पर कमजोर बना देंगी....

आवरण कथा

*****★*****

ट्रम्प 2.0

अमेरिका बनेगा

ग्रेट या गटर

*****★*****



श्रीराजेश

अमेरिका आगे तो नहीं बढ़ेगा पर वाकई 1890 के दशक में वापस पहुंच जायेगा। विदेश नीति के मोर्चे पर, ट्रंप 2.0 में मौजूदा नीतियों को अगर बढ़ावा मिलेगा तो वे अमेरिका के लिये विनाशकारी और महंगी साबित होंगी। एक वेबसाइट ग्लोबल विटनेस ओआरजी लिखता है, ट्रंप की वापसी लोकतंत्र, लोगों और पूरी धरती के लिये खतरा है....

...तमाम मीडिया सूत्र बताते हैं कि यह पर्यावरण, आर्थिकी, तकनीक विज्ञान सबके लिये नकारात्मक है, लेकिन बहुतेरे आकलन इसको गलत साबित करते हुए कहते हैं कि भले ही दुनिया के बहुत से देशों के लिये ट्रंप का दुबारा आना एक झटका हो, उनको नुकसान पहुंचे मगर ट्रंप एक बार फिर अमेरिका को महान बना देने के अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल कर लेंगे. पर क्या वाकई?

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20, जनवरी, 2025 को दूसरी बार सत्ता में आने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक घोर राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी नेता के रूप में वैश्विक स्तर पर उभरते हैं। उनके उभार से दुनिया में दक्षिणपंथी विचारधारा वाली राजनीतिक शक्तियों को सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा और दुनिया एक बार फिर आपको अलग-अलग खांचे में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते हुए नजर आएगी।

ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही धड़ाधड़ एकजक्यूटिव आर्डर पास किये, उनके इन आदेशों में व्यापार, आब्रजन, अमेरिकी विदेशी सहायता से लेकर जनसांख्यिकीय विविधता, नागरिक अधिकार और संघीय कर्मचारियों के नियुक्ति तक के विषय शामिल हैं। इनमें से कुछ का तत्काल अमेरिकी राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, अन्य अधिक प्रतीकात्मक हैं।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति के व्यापक कार्य उनके कई चुनावी वादों और देश को तेजी से दक्षिणपंथी दिशा में ले जाते हुए कार्यकारी शक्ति को पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रित करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। लेकिन इसका प्रभाव केवल अमेरिकी सीमा के भीतर ही नहीं पड़ेगा बल्कि यह दुनिया को भी समान रूप से प्रभावित करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित आब्रजन और सीमा सुरक्षा कार्यक्रम अमेरिकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास है। यह कार्यक्रम न केवल मौजूदा आब्रजन कानूनों को सख्त करता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य हस्तक्षेप और अमेरिकी नागरिकता के परिभाषित मानदंडों को भी नया रूप देने का उद्देश्य रखता है। उनके इस दृष्टिकोण को अमेरिकी सीमाओं पर हो रहे 'आक्रमण' के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि गैर-कानूनी

प्रवास और आप्रवासन नियंत्रण पर केंद्रित है।

ट्रंप का सैन्य उपयोग: पॉसे कॉमिटेट्स की चुनौती

ट्रंप के आदेश में अमेरिकी सैन्य सेवाओं को आब्रजन नियंत्रण में शामिल करने का प्रावधान है, जिसमें रेडी रिजर्व और नेशनल गार्ड को सीमा सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, सैन्य संपत्तियों का उपयोग हिरासत सुविधाओं, जमीन और हवाई परिवहन, और रसद सेवाओं के रूप में किया जाएगा। यह कदम 1878 के पॉसे कॉमिटेट्स अधिनियम से संघर्ष करता है, जो आमतौर पर घरेलू कानून प्रवर्तन कार्यों में सैन्य कर्मियों के उपयोग को सीमित करता है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है, और इसे एक सैन्य कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो कि उनके राष्ट्रपति के रूप में शक्तियों को मजबूती देता है।

ट्रंप के आदेश में 27 जनवरी 2025 तक अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को निलंबित करने की बात कही गई है। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि आब्रजन प्रणाली की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती।

जन्मसिद्ध नागरिकता की पुनर्परिभाषा: 14वें संशोधन की नई व्याख्या

ट्रंप के आब्रजन आदेशों में 14वें संशोधन के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता की पुनर्परिभाषा की गई है। अब अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा तभी नागरिक होगा, जब उसके माता-पिता कानूनी रूप से अमेरिका में स्थायी निवासी हों। यह आदेश संघीय अदालत में चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह लाखों लोगों की नागरिकता स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

शरणार्थी कार्यक्रम का निलंबन और नई जांच प्रक्रिया

ट्रंप के आदेश में 27 जनवरी 2025 तक अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को निलंबित करने की बात कही गई है। यह निलंबन



तब तक जारी रहेगा जब तक कि आब्रजन प्रणाली की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त, वीजा या अन्य आब्रजन लाभ चाहने वालों के लिए सख्त जांच प्रक्रिया लागू की जाएगी। यह प्रक्रिया ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इस्तेमाल की गई मानकों पर आधारित होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी।

अमेरिकी-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण और सुरक्षा उपाय

ट्रंप ने अमेरिकी-मेक्सिको सीमा पर दीवार और अन्य अवरोधों के निर्माण को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही, होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो आपराधिक गिरोहों और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी।

पकड़ो और छोड़ो नीति पर प्रतिबंध

ट्रंप ने तथाकथित 'पकड़ो और छोड़ो' नीति पर प्रतिबंध लगाने

की बात कही है, जिसके तहत कुछ अप्रवासियों को आब्रजन अदालत की सुनवाई तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाती है। यह नीति अब समाप्त कर दी जाएगी और सभी गैरकानूनी अप्रवासियों को हिरासत में लेकर निर्वासित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए होमलैंड सुरक्षा विभाग को नई हिरासत सुविधाओं का निर्माण करने का निर्देश दिया गया है।

पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम की समाप्ति

क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को अमेरिका लाने वाले पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम को भी समाप्त किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन इसे बंद कर उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है जो कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक प्रवास पर बाइडेन नीतियों का निरसन

ट्रंप ने बाइडेन के उस आदेश को भी निरस्त करने की योजना बनाई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते प्रवासन के पैटर्न की योजना बनाई गई थी। ट्रंप के अनुसार, यह नीति आवश्यक नहीं है और इसके बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ट्रंप ने उन गैर-सरकारी संगठनों को संघीय धन देने से मना करने का भी प्रस्ताव रखा है, जो अवैध अप्रवासियों को सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही, 'अभयारण्य' शहरों को संघीय धन से वंचित करने की योजना बनाई गई है, जो संघीय आब्रजन कानूनों को लागू करने में असफल हो रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय कार्टेलों को आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव

आब्रजन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कार्टेलों को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' या 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' घोषित करने का प्रस्ताव भी ट्रंप के आदेशों का हिस्सा है। इससे कार्टेलों पर विदेशी शत्रु अधिनियम लागू किया जाएगा, जो उनकी गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।



को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करें। इसका उद्देश्य एकीकृत अमेरिकी पहचान को बढ़ावा देना है और आव्रजन से जुड़े मुद्दों को नियंत्रित करना है।

डोनाल्ड ट्रम्प का यह आव्रजन और सीमा नियंत्रण कार्यक्रम अमेरिका की आव्रजन नीतियों को मौलिक रूप से बदलने का प्रयास है। यह नीतियां न केवल अमेरिका के नागरिकता के मानदंडों और सीमा सुरक्षा पर असर डालेंगी, बल्कि यह अमेरिका की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव छोड़ेंगी। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम में सैन्य हस्तक्षेप, नागरिक अधिकारों की पुनर्परिभाषा, और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

व्यापार एवं अर्थव्यवस्था

अब बात करें व्यापार एवं अर्थव्यवस्था की तो डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण एक व्यापक

में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाए रखने के लिए संरचित हैं, जबकि वैश्विक व्यापार प्रथाओं की समीक्षा और संभावित सुधारों की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रित करने पर जोर

ट्रम्प प्रशासन की प्राथमिकता उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रित करने की है। उन्होंने कार्यकारी एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी नीतियों को इस तरह से ढालें, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कम की जा सकें। ट्रम्प हर 30 दिनों में अपने शीर्ष आर्थिक सलाहकार से प्रगति रिपोर्ट चाहते हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि वह इस मुद्दे को किस गंभीरता से लेते हैं। उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रित करने का यह प्रयास आर्थिक स्थिरता और आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

व्यापार घाटा और अनुचित व्यापार प्रथाओं की समीक्षा

ट्रम्प प्रशासन ने वित्त और वाणिज्य सचिवों, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और अन्य विशेषज्ञों को अमेरिकी व्यापार घाटे के कारणों की जांच करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं की पहचान करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसमें 'वैश्विक पूरक टैरिफ' लागू करने की संभावना भी शामिल है, जो ट्रम्प की व्यापारिक नीतियों का एक प्रमुख हिस्सा हो सकता है। यह दृष्टिकोण घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने और वैश्विक व्यापारिक असंतुलनों को संतुलित करने के लिए किया जा रहा है। ट्रम्प ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अमेरिकी कंपनियां और उत्पादक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकें और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक विवादों को सुलझाया जा सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते की समीक्षा

NAFTA का पुनर्लेखन करते हुए ट्रम्प ने 2026 तक इस समझौते की पुनः समीक्षा करने की योजना बनाई है। इस संबंध में,

ट्रम्प ने अमेरिका की वैश्विक कर समझौते में भागीदारी को निलंबित कर दिया है। इस समझौते का उद्देश्य था कि बहुराष्ट्रीय निगम कर भुगतान से बच न सकें। ट्रम्प का यह कदम अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और अधिक लाभ देने के लिए किया गया है।

उन्होंने कनाडाई और मैक्सिकन वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह कदम अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देने और व्यापार असंतुलन को सुधारने के लिए है। हालाँकि अभी तक उन्होंने इस कदम पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन यह नीति अमेरिकी उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर उनके फोकस को दर्शाती है।

बाह्य राजस्व सेवा और टैरिफ नीतियाँ

ट्रम्प ने विदेशी व्यापार से संबंधित शुल्क और राजस्व को एकत्र करने के लिए एक 'बाह्य राजस्व सेवा' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, उन्होंने चीन के साथ व्यापार संबंधों की समीक्षा शुरू की है और चीन पर नए या बढ़े हुए टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है। ट्रम्प ने अपने चुनाव प्रचार में चीन पर 60% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, और यह प्रस्ताव अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में एक नए मोड़ को दर्शाता है।

फेंटेनाइल और व्यापार प्रतिबंध

फेंटेनाइल, जो अमेरिका में मादक पदार्थों की समस्या का प्रमुख कारण है, उस पर ट्रम्प का फोकस है। उन्होंने विशेष रूप से कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले फेंटेनाइल के प्रवाह की समीक्षा का अनुरोध किया है। उन्होंने टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, जो अमेरिका की मादक पदार्थों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक निर्णायक कदम हो सकता है।

वैश्विक कर समझौते से अलगाव

ट्रम्प ने अमेरिका की वैश्विक कर समझौते में भागीदारी को निलंबित कर दिया है। इस समझौते का उद्देश्य था कि बहुराष्ट्रीय निगम कर भुगतान से बच न सकें। ट्रम्प का यह कदम अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और अधिक लाभ देने के लिए किया गया है, जो उनके 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण के अनुरूप है।

टिकटॉक प्रतिबंध और सोशल मीडिया नीति

टिकटॉक पर अमेरिकी प्रतिबंध को 75 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। ट्रम्प ने नए प्रशासन को यह आकलन करने का मौका दिया है कि इस प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा है और संभावित अमेरिकी खरीदार की तलाश की जा रही



जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण के मुद्दों

डोनाल्ड ट्रम्प का जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण के मुद्दों पर विचार और कार्य नीतियाँ पिछले प्रशासन की नीतियों के विपरीत, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को बनाए रखने और घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। उनकी प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करने, पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करने, और पर्यावरण से संबंधित बाइडेन प्रशासन की नीतियों को पलटने पर है।

पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना ट्रम्प प्रशासन का पहला बड़ा कदम है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को नकारता है। यह कदम उनके 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण का प्रतीक है, जिसमें उनका मानना है कि पेरिस समझौता अमेरिकी आर्थिक और व्यापारिक हितों को नुकसान

पहुँचाता है, जबकि अन्य देशों को अनुचित लाभ मिलता है। ट्रम्प प्रशासन की यह नीति जलवायु परिवर्तन के खतरों की उपेक्षा करते हुए घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देती है।

राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करना एक प्रतीकात्मक कदम है, जो सरकार को निजी भूमि और संसाधनों पर कब्जा करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाना है, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधनों के मामले में। यह संकेत देता है कि ट्रम्प ऊर्जा क्षेत्र में निजी संपत्ति के अधिकारों और पर्यावरणीय सुरक्षा के बजाय घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

बाइडेन की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को समाप्त करना ट्रम्प की

जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता की नीति का हिस्सा है। जबकि बाइडेन प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने का प्रयास किया, ट्रम्प की यह नीति पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करती है। ट्रम्प मानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना अमेरिकी पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर करेगा, जबकि जीवाश्म ईंधन उद्योग अमेरिकी नौकरियों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।

अलास्का में जीवाश्म ईंधनों के निष्कर्षण में तेजी और आर्कटिक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य के भीतर पट्टों की बहाली ट्रम्प प्रशासन के पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। आर्कटिक क्षेत्र, जो कि जीवाश्म ईंधन का प्रमुख स्रोत हो सकता है, को ट्रम्प प्रशासन ने आर्थिक अवसर के रूप में देखा। यह कदम पर्यावरणीय संगठनों के लिए चिंता का विषय है, जो इसे इस क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण और स्वदेशी समुदायों के लिए हानिकारक मानते हैं।

विनियमों को रद्द करना और शिकार पर पुराने नियमों की बहाली अलास्का जैसे राज्यों में अधिक पारंपरिक भूमि उपयोग की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि राज्य की सरकारें अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं, और उन्हें संघीय कानूनों और नियमों के तहत सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। यह नीति शिकार और मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने की कोशिश करती है, जो कई ग्रामीण समुदायों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं।

पवन ऊर्जा विकास पर प्रतिबंध और बाह्य महाद्वीपीय शेल्फ को पवन ऊर्जा पट्टों के लिए अयोग्य बनाना अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर लगाए गए प्रतिबंधों को दर्शाता है। यह नीति ट्रम्प के जीवाश्म ईंधन केंद्रित दृष्टिकोण को बल देती है, जबकि जलवायु वैज्ञानिकों और पर्यावरण संरक्षण संगठनों ने बार-बार इसे जलवायु संकट से लड़ने के लिए आवश्यक कदम के रूप में चिह्नित किया है।

संक्षेप में, ट्रम्प की जलवायु और ऊर्जा नीतियाँ अमेरिका के पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों और उद्योगों को संरक्षित करने पर केंद्रित हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को कम महत्व देती हैं। ये नीतियाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाने के इरादे से बनाई गई हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय और वैश्विक परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

ट्रांसजेंडर एवं नागरिक अधिकार

ट्रम्प प्रशासन द्वारा घोषित इन नीतियों का गहन विश्लेषण उनकी विचारधारा और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की दिशा को दर्शाता है। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि विविधता, समानता, और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों के खात्मे का निर्णय समाज में पहले से चले आ रहे प्रगतिशील बदलावों को रोकने का प्रयास है। सरकारी विभागों और एजेंसियों में 'मुख्य विविधता अधिकारी' और 'समानता कार्य योजनाओं' को हटाने का आदेश इस बात का संकेत है कि ट्रम्प प्रशासन एक समरूप, परंपरागत ढांचे पर जोर देता है, जिसमें व्यक्तिगत पहचान और भिन्नता की बजाय एक अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

DEI से जुड़ी नीतियों और ठेकेदारों पर 60 दिन की समय सीमा रखी गई है, जो प्रशासन की तीव्रता को दिखाता है। इसके अलावा, नस्लीय, जातीय और LGBTQ अधिकारों पर बाइडेन के निर्देशों को निरस्त करना एक स्पष्ट संदेश देता है कि ट्रम्प प्रशासन पारंपरिक मान्यताओं और संरचनाओं पर जोर देता है, खासकर जेंडर और लिंग पहचान के मुद्दों पर। यह LGBTQ समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है, जो बाइडेन प्रशासन के समय में कई अधिकार और समावेशी नीतियों का लाभ उठा रहा था।

पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना ट्रम्प प्रशासन का पहला बड़ा कदम है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को नकारता है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी दस्तावेजों में केवल दो लिंगों को मान्यता देना और 'लिंग पहचान' की अवधारणा को अस्वीकार करना, प्रशासन की स्पष्ट दृष्टिकोण को रेखांकित करता है कि वे लिंग की परिभाषा को जैविक और पारंपरिक मानते हैं। इसका प्रभाव स्कूलों और जेलों में भी देखा जाएगा, जहां ट्रांसजेंडर लोगों के

लिए पहले से बनाए गए समावेशी प्रावधान हटा दिए जाएंगे।

संघीय कर्मचारी और सरकार की संरचना

इस नीति प्रस्ताव का विश्लेषण ट्रम्प प्रशासन की सरकारी संरचना और संघीय कर्मचारियों पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सबसे प्रमुख पहलू है 'सरकारी दक्षता विभाग' की स्थापना, जिसे एलन मस्क की अगुवाई में किया जाएगा। मस्क के नेतृत्व में, इस विभाग का उद्देश्य संघीय कार्यक्रमों और व्यय में कटौती करना है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन व्यय में कमी और सरकारी दक्षता में सुधार को प्राथमिकता दे रहा है।

प्रत्येक एजेंसी प्रमुख को अपनी 'DOGE टीम' बनानी होगी,

जो मस्क के साथ काम करेगी। यह एक केंद्रीय दृष्टिकोण है, जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों को निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता और दक्षता की दिशा में प्रेरित करता है। संघीय भर्तियों पर प्रतिबंध, कुछ अपवादों के साथ, सरकारी कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने और सरकारी खर्च में कटौती के प्रयास का हिस्सा है। हालांकि, यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा, आब्रजन, और सैन्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, जिससे सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को संरक्षित किया जाएगा।

संघीय नियमों और विनियमों पर प्रतिबंध, खासकर उन एजेंसियों में जहां ट्रम्प द्वारा नियुक्त अधिकारी मौजूद नहीं हैं, प्रशासन की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को और अधिक नियंत्रित करने का प्रयास है।

इसके साथ ही, सभी संघीय कर्मचारियों को पूर्णकालिक रूप से काम पर लौटने का निर्देश और वरिष्ठ कार्यकारी सेवा (SES) अधिकारियों की समीक्षा प्रशासन के अधिक पारदर्शी नियंत्रण की दिशा में एक कदम है। इस नीति के तहत SES अधिकारियों को राष्ट्रपति की नीतियों के प्रति वफादार रहना होगा, और यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, संघीय कर्मचारियों की नियुक्ति में 'संविधान के प्रति समर्पण' को प्राथमिकता देना प्रशासन की उस धारणा को दर्शाता है कि सरकारी सेवा में कार्य करने वाले लोग अमेरिका के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए।

संक्षेप में, यह नीतिगत दृष्टिकोण सरकारी दक्षता, नियंत्रण, और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि पारंपरिक भर्तियों और संरचनाओं में बदलाव की दिशा में संकेत करता है।

स्वास्थ्य देखभाल

स्वास्थ्य देखभाल पर ट्रम्प प्रशासन की यह नीति विश्लेषण कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है, जो बाइडेन प्रशासन की प्राथमिकताओं से अलग दिशा में जाती है। ट्रम्प प्रशासन की योजना बाइडेन के निर्देशों को निरस्त करने पर केंद्रित है, जो मेडिकेड में नामांकन को सरल बनाते हैं, अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत बीमा कवरेज की गारंटी देते हैं, और दवा की लागत को कम करने के प्रयासों पर आधारित हैं। बाइडेन की नीतियां लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को आसान बनाने और चिकित्सा खर्च को कम करने पर केंद्रित थीं।

हालांकि, ट्रम्प का प्रस्ताव इंसुलिन पर बाइडेन द्वारा निर्धारित \$35 की मासिक सीमा या मेडिकेयर की प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर वार्षिक \$2,000 की आउट-ऑफ-पॉकेट सीमा जैसी महत्वपूर्ण



नीतियों को खत्म नहीं करता है। ये नीतियां कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के तहत हैं और ट्रम्प प्रशासन द्वारा रद्द नहीं की जा सकतीं, जिससे यह संकेत मिलता है कि बाइडेन की कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नीतियां बरकरार रहेंगी।

इसके अलावा, ट्रम्प की नीति COVID-19 से संबंधित बाइडेन के कई आदेशों और निर्देशों को निरस्त करने पर केंद्रित है। इस उपाय का उद्देश्य महामारी के दौरान बाइडेन द्वारा लागू किए गए सख्त नियमों को वापस लेना है, जो सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रहे थे। यह कदम एक अधिक सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में संकेत करता है, जहां कोविड-19 के निर्देशों को कम करके अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

इस प्रकार, ट्रम्प प्रशासन की ये नीतियां स्वास्थ्य सेवा में बाइडेन के सुधारों को सीमित करते हुए एक स्वतंत्र बाजार और कम सरकारी हस्तक्षेप की दिशा में संकेत करती हैं। हालांकि, कुछ प्रमुख दवा कीमत नियंत्रण और मेडिकेयर से जुड़ी नीतियों को बदलने की संभावना न होने से यह भी स्पष्ट है कि सभी बड़े बदलाव तुरंत

ट्रम्प प्रशासन की नीतियां स्वास्थ्य सेवा में बाइडेन के सुधारों को सीमित करते हुए एक स्वतंत्र बाजार और कम सरकारी हस्तक्षेप की दिशा में संकेत करती हैं। हालांकि, कुछ प्रमुख दवा कीमत नियंत्रण और मेडिकेयर से जुड़ी नीतियों को बदलने की संभावना न होने से यह भी स्पष्ट है कि सभी बड़े बदलाव तुरंत संभव नहीं हैं।

संभव नहीं हैं।

राष्ट्रवाद और प्रतीकात्मकता

डोनाल्ड ट्रम्प का राष्ट्रवाद पर जोर उनकी नीति और प्रतीकात्मक निर्णयों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका उदाहरण अलास्का में माउंट मैकिनले का नाम पुनः स्थापित करने का उनका निर्णय है, जो अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले को श्रद्धांजलि देता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने पर्वत का नाम डेनाली रखा था, जो ऐतिहासिक रूप से मूल जनजातियों द्वारा दिया गया नाम था। इस निर्णय के पीछे ट्रम्प की मंशा अमेरिका के राष्ट्रवादी गौरव और उसके ऐतिहासिक नेताओं को मान्यता देने की थी। हालांकि, उनके आदेश में डेनाली राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र का नाम नहीं बदला गया, जो स्थानीय जनजातियों की ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान बना रहने का संकेत देता है।

इसके अलावा, ट्रम्प ने संघीय भवनों के लिए नए वास्तुशिल्प मानकों की मांग की, ताकि अमेरिका की शास्त्रीय और पारंपरिक वास्तुकला की धरोहर को संरक्षित और सम्मानित किया जा सके। इस आदेश के पीछे उनका उद्देश्य था कि संघीय इमारतें अमेरिकी

सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान दें और सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाएं। यह ट्रम्प की राष्ट्रवादी विचारधारा का एक और प्रतीकात्मक कदम है, जो अमेरिका की क्षेत्रीय और पारंपरिक धरोहर को संरक्षित करने की उनकी मंशा को दर्शाता है।

मृत्युदंड और अपराध नीति

ट्रम्प का दृष्टिकोण कानून व्यवस्था के पक्ष में स्पष्ट रूप से झुका हुआ है। उनके निर्देशों में अटॉर्नी जनरल को यह जांच करने का आदेश दिया गया था कि उन 37 संघीय कैदियों पर फिर से राज्य अदालतों में मृत्युदंड संबंधी अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, जिनकी सजा बाइडेन ने आजीवन कारावास में बदल दी थी। इसके अलावा, उन्होंने घातक इंजेक्शन के लिए उपयुक्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'सभी आवश्यक और कानूनी उपाय' करने का निर्देश दिया।

ट्रम्प की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों को पलटने के प्रयास का निर्देश दिया, जो राज्य और संघीय क्षेत्रों में मृत्युदंड के उपयोग को सीमित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य अटॉर्नी जनरल और जिला अटॉर्नी को सभी संभावित मामलों में मृत्युदंड की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करने का आदेश भी दिया। यह कदम उनके कानून व्यवस्था के प्रति सख्त दृष्टिकोण को दर्शाता है और अपराध के प्रति उनकी कठोर नीतियों का समर्थन करता है।

कैपिटल दंगा और 2020 चुनाव

कैपिटल दंगे के बाद ट्रम्प के फैसले उनकी राजनीतिक विचारधारा और उनके समर्थकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। उन्होंने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल पर हुए हमलों के लिए दोषी ठहराए गए सैकड़ों लोगों की सजा को कम करने और उन्हें पूर्ण क्षमा प्रदान करने की घोषणा की। इसके पीछे ट्रम्प का तर्क था कि यह हमले उनके खिलाफ हुई चुनावी धांधली के परिणामस्वरूप थे, जिसे उन्होंने 'संघीय सरकार के हथियारीकरण' के रूप में वर्णित किया।

उन्होंने अटॉर्नी जनरल और अन्य अधिकारियों को बाइडेन के कार्यकाल के दौरान की गई जांचों और प्रवर्तन कार्रवाइयों की समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके समर्थकों के खिलाफ कोई अनुचित कार्रवाई न की गई हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ अमेरिकी सरकार के व्यवहार की जांच के निर्देश भी दिए, जिसे ट्रम्प ने सेंसरशिप प्रयासों के रूप में वर्णित किया था। इस जांच के तहत 'उचित सुधारात्मक कार्रवाई' की सिफारिश करने के आदेश दिए गए।

ट्रम्प ने उन 50 लोगों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी, जिन्होंने बाइडेन के 2020 अभियान के साथ हंटर बाइडेन के लैपटॉप मामले पर सहयोग किया था। यह निर्णय उन खुफिया अधिकारियों पर आरोप लगाकर किया गया, जिन्होंने कथित तौर पर चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास किए थे। ट्रम्प ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और सीआईए के निदेशक को 90 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश की गई हो।

निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां राष्ट्रवाद, अपराध नियंत्रण, और 2020 चुनाव से जुड़े विवादों पर आधारित हैं। उन्होंने अमेरिकी धरोहर और परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से माउंट मैकिनले का नाम पुनः स्थापित किया और संघीय भवनों के वास्तुशिल्प मानकों को भी ऊंचा उठाने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने मृत्युदंड को फिर से लागू करने के प्रयास किए और कानून व्यवस्था के पक्ष में कठोर नीतियों को बढ़ावा दिया। कैपिटल दंगे और 2020 के चुनाव के संदर्भ में, ट्रम्प ने अपने समर्थकों की रक्षा करने और बाइडेन प्रशासन की नीतियों की समीक्षा कराने का प्रयास किया। उनके ये निर्णय उनके राष्ट्रवादी और कठोर कानून व्यवस्था के रुख को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।



ट्रम्प 2.0

'अमेरिका फर्स्ट'

या

निरंतरता का रास्ता?



श्रीराजेश

इस आलेख में हम ट्रंप और बाइडेन की विदेश नीतियों की तुलना करेंगे और यह विश्लेषण करेंगे कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किस प्रकार के बदलाव और निरंतरताएँ देखने को मिल सकती हैं।



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सत्ता में लौटे हैं। दुनिया भर में उनकी नई विदेश नीति किस दिशा की ओर इशारा करती है, चर्चा तेज हो गई है। उनके पूर्ववर्ती, जो बाइडेन, के शासन के दौरान जहां एक ओर लोकतंत्र और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया, वहीं ट्रंप ने 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति को प्राथमिकता दी थी। दोनों नेताओं के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है, लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में निरंतरता बनी रहती है। भले ही प्रत्येक राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और शैली में अंतर रखते हों, लेकिन यह निरंतरता मुख्यतः अमेरिका की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं से उत्पन्न होती है। राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक स्थिर मार्ग का पालन करता है।

ट्रंप और बाइडेन की विदेश नीति में प्रमुख अंतर:

बाइडेन के कार्यकाल में, अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया, ताइवान की रक्षा का संकल्प लिया, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया, और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और चीन के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ को प्राथमिकता दी। बाइडेन की सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि अमेरिका का वैश्विक नेतृत्व कायम रहे, और उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से वापसी की।

वहीं, ट्रंप के दृष्टिकोण में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के समर्थन पर प्रश्न उठाया, ताइवान के मामले में संकोच दिखाया, जलवायु परिवर्तन को नकारा और मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में रुचि कम दिखाई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा खर्च में अपने सहयोगियों द्वारा योगदान को लेकर आलोचना की और चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए। ट्रंप का यह मानना था कि अमेरिका को अपने हितों को पहले रखना चाहिए और जो भी वैश्विक सहयोग हो,

उससे अमेरिका को ठोस लाभ मिलना चाहिए।

ट्रंप और बाइडेन के शासनकाल में निरंतरता:

हालाँकि, विदेश नीति के क्षेत्रों में काफी भिन्नताएँ हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में निरंतरता भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, बाइडेन ने चीन और रूस को अमेरिका के सबसे बड़े वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के रूप में पहचाना, जो ट्रंप की नीति का हिस्सा था। इसके अलावा, बाइडेन ने ट्रंप द्वारा लगाए गए चीन पर टैरिफ और तकनीकी नियंत्रण को बरकरार रखा। बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ट्रंप द्वारा की गई समझौते के तहत पालन किया, और यूक्रेन को लेथल सहायता भी दी, जैसा कि ट्रंप के शासन में किया गया था।

इसके अतिरिक्त, बाइडेन ने अब्राहम समझौतों (Abraham Accords) को आगे बढ़ाया, जो ट्रंप प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थी। बाइडेन ने सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की, जो ट्रंप के समय से ही एक अहम मुद्दा था। इसलिए, बाइडेन और ट्रंप की नीतियों में भले ही शैलियों में अंतर हो, लेकिन मूल नीति में निरंतरता देखी गई है।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में संभावित बदलाव:

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले, अमेरिका के सहयोगियों के साथ रिश्तों में एक कठोर दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में यह दावा करते थे कि कई देशों ने अमेरिका की सुरक्षा में मुफ्त लाभ उठाया है, और वह इसे बदलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, उनका ध्यान हमेशा व्यापार घाटों और आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर रहा है, खासकर चीन के साथ। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह नीति और भी सख्त हो सकती है।

चीन के संदर्भ में, ट्रंप प्रशासन संभवतः चीन को अमेरिकी आर्थिक और सुरक्षा हितों के खिलाफ एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखेगा। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप अमेरिका के साझेदारों के साथ मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि भारत, जापान, और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका एक उदाहरण क्वाड (Quad) और ऑकस (AUKUS) जैसे रक्षा समझौते हैं, जो ट्रंप के समय में शुरू हुए थे और बाइडेन प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ाया।

शैली में अंतर और समानताएँ:

ट्रंप और बाइडेन के विदेश नीति में शैली का अंतर स्पष्ट है। ट्रंप को एकतरफा निर्णय लेने वाला और अपने साथी देशों के साथ ज्यादा संवाद न करने वाला नेता माना जाता है, जबकि बाइडेन ने अपने



सहयोगियों के साथ परामर्श और कंसल्टेशन पर जोर दिया। ट्रंप अपनी नीतियों को ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करते थे, जबकि बाइडेन अधिक परंपरागत कूटनीतिक तरीकों को अपनाते हैं। फिर भी, बाइडेन प्रशासन ने भी कई मामलों में एकतरफा फैसले लिए हैं, जैसे कि चीनी तकनीकी कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण लगाना।

विदेश नीति की स्थिरता:

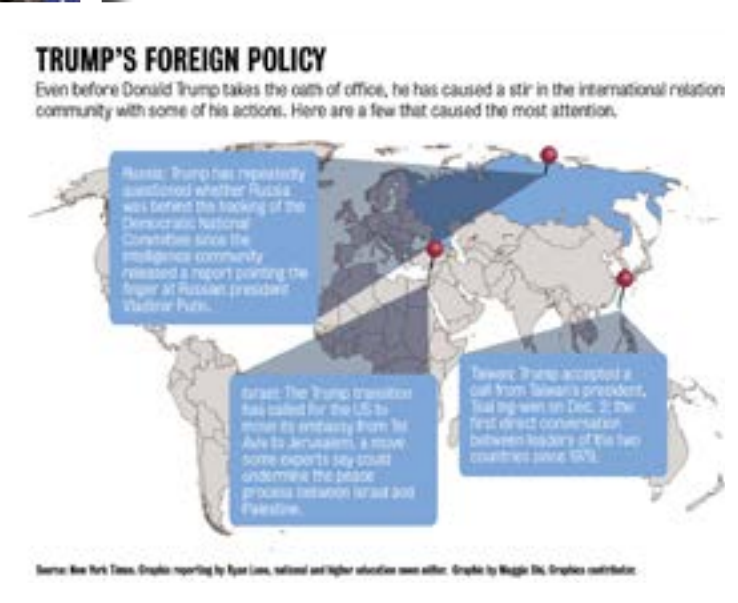
विभिन्न प्रशासनों में विदेश नीति में बदलाव होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ओबामा ने जॉर्ज बुश के 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' की आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने भी बुश से अधिक देशों में सैन्य कार्रवाई की। इसी प्रकार, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अभियान में NAFTA और अमेरिका-कोरिया मुक्त व्यापार समझौते की आलोचना की, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने उनके संशोधित संस्करणों पर हस्ताक्षर किए। यह बताता है कि, भले ही राष्ट्रपति चुनावी वादों के दौरान नीतियों को बदलने का वादा करते हैं, वास्तव में प्रशासन में बदलाव के बावजूद कई क्षेत्र समान रहते हैं।

स्थिर अमेरिकी हित:

अमेरिका के विदेश नीति के कई कारक समय के साथ स्थिर रहते हैं, जैसे कि यूरोएशिया में एक शत्रुतापूर्ण शक्ति का प्रभुत्व न होने देना, समुद्री स्वतंत्रता की रक्षा करना (जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है), मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखना, और इस्राइल का समर्थन करना। इन स्थिर हितों के कारण, अमेरिकी नीति में परिवर्तनशीलता कम होती है, और यह हर राष्ट्रपति के तहत अधिक या कम समान रहती है।

नियमित अमेरिकी हस्तक्षेप:

अमेरिका की विदेश नीति में कई क्षेत्रों में निरंतरता है। उदाहरण



के लिए, क्यूबा में राजनीतिक परिवर्तन लाने की नीति राष्ट्रपति आइज़नहावर से ही चली आ रही है। NATO देशों को रक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करने की नीति राष्ट्रपति केनेडी से जारी है। साथ ही, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने हितों की रक्षा करने के लिए सैन्य ताकत का उपयोग किया है, जो कि राष्ट्रपति जिमी कार्टर से लेकर अब तक जारी है। इसके अलावा, नॉर्थ कोरिया के साथ वार्ता, इजरायल-फिलिस्तीनी शांति प्रक्रिया, और मिसाइल रक्षा योजनाएं सभी अमेरिकी प्रशासनों में एक समान रही हैं।

कांग्रेस की भूमिका:

अमेरिकी कांग्रेस विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, ताइवान से पेइचिंग को मान्यता देने के बाद, कांग्रेस ने ताइवान संबंध कानून (Taiwan Relations Act) पारित किया, जिसने ताइवान के समर्थन की गारंटी दी। इसी तरह, जब राष्ट्रपति कार्टर ने 1977 में दक्षिण कोरिया से अमेरिकी बलों को हटाने की योजना बनाई थी, तो कांग्रेस ने हस्तक्षेप किया।

इसी प्रकार, जब ट्रंप ने रूस के प्रति गर्मजोशी दिखाई, तो कांग्रेस ने ओबामा-कालीन कार्यकारी आदेशों को कानूनी रूप में लागू किया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निरंतरता:

अमेरिका का विदेश नीति ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि मुख्य विदेशी सहयोगी देशों के साथ संबंध हमेशा बनाए रहें। उदाहरण के तौर पर, इजरायल, सऊदी अरब और चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में भले ही विभिन्न प्रशासनों में दृष्टिकोण अलग-अलग हो, लेकिन उनके साथ संवाद और सहयोग का सिलसिला हमेशा कायम रहा है। चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, अमेरिका ने हमेशा चीन को वैश्विक चुनौती के रूप में देखा और सऊदी अरब से अपने रणनीतिक संबंधों को जारी रखा।

विदेश नीति में व्यक्तित्व का प्रभाव:

यह लेख यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व शैली का भी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण

चलता। उदाहरण के लिए, NATO से बाहर निकलने के बजाय, एक राष्ट्रपति केवल यह संकेत दे सकता है कि वह किसी सहयोगी देश की रक्षा नहीं करेगा यदि वह हमले का शिकार होता है। यह एक प्रकार से नीति को नुकसान पहुँचाने का तरीका है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता को चुनौती देता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बदलता नहीं है। इसी प्रकार, यदि कोई राष्ट्रपति जापान से असंतुष्ट होता है, तो वह अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति को लेकर दबाव बना सकता है।

क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ:

ओबामा और बाइडेन ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अमेरिकी विदेश नीति में प्राथमिकता दी, वैसे ही ट्रंप प्रशासन भी इस क्षेत्र को अपने विदेश नीति के एजेंडे में शामिल कर सकता है। हालांकि, यह क्षेत्रीय प्राथमिकता चुनौतियों से भरी होती है, जैसे कि चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को संभालना।

संघर्ष से बचाव की नीति:

अंत में, विदेश नीति में यह भावना बनी रहती है कि अमेरिकी प्रशासन सैन्य संघर्षों से बचने की कोशिश करता है। जैसे बाइडेन ने रूस, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में सैन्य संघर्ष से बचने की कोशिश की, वैसे ही ट्रंप भी अपनी रणनीति में इस तरह के संघर्षों से बचने का प्रयास कर सकते हैं।

के लिए, ओबामा और ट्रंप दोनों की विदेश नीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई मूल नीति में ज्यादा अंतर नहीं था। ट्रंप और बाइडेन दोनों ने व्यक्तिगत रिश्तों की शक्ति पर जोर दिया, हालांकि उनका तरीका भिन्न था। ट्रंप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जबकि बाइडेन ने अधिक पारंपरिक कूटनीतिक विधियों को अपनाया।

नीति में परिवर्तन की सीमाएँ:

राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, अमेरिका की विदेश नीति में मौलिक बदलाव करने के लिए केवल शब्दों और धमकियों से काम नहीं

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, जो कि उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत होगा। जहां बाइडेन ने वैश्विक सहयोग, लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं ट्रंप का ध्यान मुख्य रूप से अमेरिका के आर्थिक और सुरक्षा हितों पर होगा। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण में बड़े अंतर हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में निरंतरता भी देखने को मिलती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वैश्विक कूटनीति में कैसे बदलाव आते हैं और उनका नेतृत्व अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए क्या नई दिशा तय करता है।

ट्रम्प 2.0

स्वच्छ ऊर्जा से आर्थिक विकास क्या ट्रंप तैयार हैं?

लॉस एंजिल्स में फैली व्यापक जंगलों की आग जलवायु परिवर्तन के तेजी से बढ़ते और घातक प्रभावों का एक और भयावह उदाहरण है। जो लोग जलवायु परिवर्तन को नकारते हैं, वे भ्रमित हैं और असीम पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं, विशेषकर यदि वे किसी शक्तिशाली पद पर हों, जैसे ट्रंप, जिनके द्वारा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुए नुकसान को रोकने या उसे रोकने के प्रयासों में बाधा डाली जा सकती है।

ट्रंप, जो आर्थिक विकास के हिमायती हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर पुनः विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इसे संबोधित करके स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए नए व्यवसाय और लाखों नौकरियां उत्पन्न कर विशाल आर्थिक विकास के अवसर कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था



14 जनवरी, 2025 तक, लॉस एंजिल्स में जंगल की आग ने पहले ही 25 लोगों की जान ले ली (जिसमें ईटन आग में 17 और पैलिसेड्स आग में 8 लोग शामिल हैं) और अब तक यह लगभग \$250 से \$275 बिलियन तक का नुकसान कर सकती है। 12,000 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गईं, और इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी और घातक अग्निकांड में से एक माना जा रहा है।

केवल पैसिफिक पैलिसेड्स में, कैलिफोर्निया ने 5,316 संरचनाओं के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की सूचना दी है। ये आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि आलेख लिखे जाने तक आग जारी है।

जो लोग जलवायु परिवर्तन को एक धोखा मानते हैं, वे कई निर्विवाद तथ्यों को नकार नहीं सकते, जो दशकों के अनुसंधान और स्पष्ट प्रमाणों पर आधारित हैं, जिनमें बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, पौधों और जानवरों के व्यवहार में बदलाव, और वैश्विक तापमान में लगभग 1C की वृद्धि शामिल है, जो 1880 के बाद से हुई है।

यह संख्या, जो छोटी सी प्रतीत होती है, आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है; 2017 के एक अध्ययन में पाया गया था कि हर 1C तापमान वृद्धि के साथ, अमेरिका को अपनी GDP का 2.3% खोने का खतरा होता है।

हालांकि, इससे पहले कि हम जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के द्वारा नए उद्योगों को विकसित कर आर्थिक विकास की संभावनाओं की जांच करें, यह आवश्यक है कि हम पिछले चार वर्षों में केवल छह विनाशकारी घटनाओं द्वारा उत्पन्न किए गए विशाल नुकसान और मृत्यु दर पर ध्यान दें, जो यूएस में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य कई आपदाओं के बीच घटित हुई।

अगस्त 2020 में, तूफान लौरा एक शक्तिशाली श्रेणी 4 तूफान था, जिसने 15 फीट से अधिक की तूफान की लहरें और 150 मील प्रति घंटा की ऐतिहासिक हवाओं की गति उत्पन्न की, जो 1856 के बाद से सबसे तेज़ थी। इसने 42 मौतें और \$28.1 बिलियन का



अलोन बेन-मीर

नुकसान किया।

अगस्त से दिसंबर 2020 तक, कैलिफोर्निया, ओरेगन, और वाशिंगटन में बड़े पैमाने पर आग के तूफानों ने 46 मौतें और \$19.9 बिलियन का नुकसान किया। इन आगों ने कई छोटे शहरों को नष्ट कर दिया और महीनों तक लाखों लोगों को गंभीर वायु गुणवत्ता से प्रभावित किया।

अगस्त 2021 में तूफान इडा ने 96 जानें लीं और \$84.6 बिलियन का नुकसान किया। यह तूफान लुइसियाना से न्यू यॉर्क तक फैला और इसे पांचवें और सातवें सबसे महंगे उष्णकटिबंधीय तूफान के बीच माना जाता है।

फरवरी 2021 में, एक ऐतिहासिक ठंडी लहर और सर्दी का तूफान जिसने अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित किया, 262 मौतों और \$27.2 बिलियन के नुकसान का कारण बना, यह अब तक का सबसे महंगा शीतकालीन तूफान था। टेक्सास इस तूफान से सबसे अधिक प्रभावित राज्य था, जहां अधिकांश मौतें (210) हुईं।

सितंबर 2024 में, श्रेणी 4 का तूफान हेलिन फ्लोरिडा के बिग बेंड क्षेत्र में 140 मील प्रति घंटा से अधिक की हवाओं के साथ आया। इस चक्रवात ने \$78.7 बिलियन का नुकसान किया और 219 लोगों की जान ली। इसने 15 फीट से अधिक की तूफान की लहर और 30 इंच से अधिक की ऐतिहासिक बारिश उत्पन्न की, जिसके कारण पश्चिमी नॉर्थ कैरोलिना में भारी बाढ़ आई।

अंततः, अक्टूबर 2024 में, तूफान मिल्टन, जो श्रेणी 3 से श्रेणी 5 में तेजी से विकसित हुआ, ने 32 जानें लीं और \$35 बिलियन के लगभग नुकसान का कारण बना। इसने फ्लोरिडा में भूमि पर आगमन किया और कई टॉरनेडो उत्पन्न किए, जिससे हेलिन से हुए नुकसान में और वृद्धि हुई।

इन छह जलवायु परिवर्तन से संबंधित तूफानों और लॉस एंजिल्स की आग ने 722 मौतों का कारण बना और \$523 बिलियन

से अधिक का नुकसान किया, इसके साथ उन हजारों लोगों का अप्रत्याशित दर्द और संकट भी था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, साथ ही सैकड़ों हजारों लोग जिन्होंने पुनर्वास के लिए मजबूर होकर अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कष्टदायक और महंगी प्रक्रिया से गुजरा।

हालाँकि आग और तूफान प्राकृतिक घटनाएँ हैं और ये आगे भी घटित होंगे, जलवायु परिवर्तन ने उनकी तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिससे मृतकों की संख्या और पुनर्निर्माण पर खर्च होने वाली अरबों की राशि बढ़ गई है। कल्पना करें कि यदि इन आपदाओं से हुए \$523 बिलियन के नुकसान का केवल आधा हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा उद्योग में निवेश किया जाता तो कितने नए स्वच्छ ऊर्जा व्यवसाय बन सकते थे।

समय बहुत पहले ही पार हो चुका है, जब तक जो लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह वास्तविक है और इसे केवल स्वयं धीमा या उलट नहीं किया जा सकता। भविष्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित तूफान और आग केवल और बढ़ेंगे, जिसके साथ खरबों का खर्च और हजारों की मौतें होंगी।

जो लोग जलवायु परिवर्तन को नकारते हैं, उन्हें यह भी समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन का आक्रामक और निरंतर समाधान व्यापारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, विशेष रूप से जीवाश्म तेल और गैस उत्पादन क्षेत्रों में, बल्कि इसके विपरीत। यह नए व्यवसायों को उत्पन्न करेगा जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए समर्पित होंगे, और तेल और गैस कंपनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन करके, और इससे भी अधिक मुनाफा कमा सकती हैं।

अमेरिका के पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने वाले नए उद्योगों का निर्माण और मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने के लिए आवश्यक संसाधन और वैज्ञानिक ज्ञान है। इस विशेष क्षण में, आने वाली ट्रंप प्रशासन को राज्यों के साथ सहयोग करके स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों में निवेश के लिए संघीय फंडिंग प्रदान करनी चाहिए।

इसमें लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण के लिए आयरन-एयर बैटरियों का निर्माण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्माण (जिसे बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का विश्वास है), सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विशाल विस्तार, सभी नई उपयोगिता जनरेशन क्षमता को बढ़ाना, और स्थल और अपतटीय पवन टरबाइन निर्माण सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

अंत में, इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण और अधिक ऊर्जा-कुशल परिवहन के विकास से कार्बन उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से घटाया जा सकता है।

इन सभी प्रयासों का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को प्रि-इंडस्ट्रियल स्तरों से 1.5C के भीतर रखा जाए जैसा कि पेरिस समझौते में निर्धारित किया गया है, बल्कि यह भी कि नौकरी निर्माण में एक नाटकीय वृद्धि हो। विश्व आर्थिक मंच की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स' रिपोर्ट के अनुसार, नई नवाचारों से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में कई नौकरियों के अवसर उत्पन्न होंगे, जो न केवल जीवाश्म तेल और गैस के उपयोग को सीमित करने से होने वाली नौकरियों की हानि को संतुलित करेंगे, बल्कि 78 मिलियन नई नौकरियाँ जोड़ेंगे।

हाउस और सीनेट के कई रिपब्लिकन स्वच्छ ऊर्जा में सैकड़ों अरब डॉलर का राष्ट्रीय निवेश करने के लिए एक पहल का समर्थन करेंगे, यदि ट्रंप यह संकेत देते हैं कि वह इस प्रकार की विधानसभाओं का समर्थन करेंगे, बशर्ते जीवाश्म ईंधन और गैस उद्योग पर नए प्रतिबंधों का समान रूप से आदेश नहीं दिया जाए।

ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी में शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव और उनके अप्रत्याशित स्वभाव को देखते हुए, वह अपना विचार बदल सकते हैं जैसा कि उन्होंने कई बार किया है, बिना गंभीर विरोध का सामना किए ऐसे कानूनों को पारित करने के लिए। और इस संदर्भ में, वह डेमोक्रेट्स के लगभग सर्वसम्मत समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं।

कई लोग असहमत होंगे और यह कहेंगे कि ट्रंप की जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक स्थिति को देखते हुए, उनके विचार बदलने की कोई संभावना नहीं है। शायद ऐसा हो। हालांकि, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि ट्रंप एक कठोर रिपब्लिकन विचारधारा के समर्थक नहीं हैं। वह कट्टरपंथी नहीं हैं और जलवायु परिवर्तन संबंधी कानूनों को अपनाएंगे यदि यह आर्थिक विस्तार और लाखों नई नौकरियाँ उत्पन्न करने की गारंटी प्रदान करता है, जो उनके आर्थिक एजेंडे के दिल में है।

लेखक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, जिन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स में पढ़ाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और मध्य पूर्व अध्ययन पर पाठ्यक्रम पढ़ाए हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी उनकी वेबसाइट www.alonben-meir.com पर उपलब्ध है।

बाइडेन असफल रहे ट्रंप एक आपदा होंगे



ओमार एल अक्काद

नए साल की शुरुआत में, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान – प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम – प्रदान करने वालों की घोषणा की गई। इस साल सम्मानित होने वालों में जोस एंड्रेस शामिल थे, जो स्पेन-अमेरिकी शेफ और मानवतावादी हैं। उनकी संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन दुनियाभर में जीवनरक्षक कार्य कर रही है, हाल ही में गाजा में विशेष रूप से चर्चा में रही। अपनी उपलब्धियों को याद करते हुए, श्री एंड्रेस ने वह बात दोहराई जो उन्हें 1993 में अमेरिका आने पर तत्कालीन सीनेटर डेनियल पैट्रिक मोयनिहान ने कही थी: 'यदि तुम अमेरिका से प्यार करोगे, तो अमेरिका भी हमेशा तुम्हें प्यार करेगा।' उन्होंने व्हाइट हाउस के एक समारोह में भाग लिया, जहाँ कई नामचीन हस्तियां मौजूद थीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्री एंड्रेस की उपलब्धियों और उनके अनुकरणीय कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

यह अमेरिका के मौजूदा विभाजनकारी दौर का सबसे उपयुक्त परिदृश्य था: अमेरिका का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को पदक पहना रहा था, जिसकी संस्था के कर्मचारी उस नरसंहार में मारे गए थे, जिसका समर्थन और वित्तपोषण उसी राष्ट्रपति ने किया था। सब तरफ मुस्कराते चेहरे थे, मानो मरे हुए लोग इस क्षण को खराब करने के लिए कहीं दूर थे।

20 जनवरी, बाइडेन का एक भयावह और विवादास्पद राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ, और व्हाइट हाउस में उनका स्थान एक ऐसे व्यक्ति ने लिया है, जिसे शायद अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति के रूप में जाना जाएगा। यह एक और दौर की शुरुआत है, जहां अमेरिका असंतुलन से उन्माद की ओर जा रहा है।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर चिंता और निराशा

पिछली बार, 2016 में, गुस्से से लोग उबल पड़े थे। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, यह अविश्वास और गुस्से से भरा था कि



कोई ट्रंप जैसा व्यक्ति सिर्फ एक दिखावटी प्रचार अभियान चला सकता है, न कि राष्ट्रपति चुनाव जीत सकता है। लेकिन इस बार ऐसा कहना मुश्किल है कि 'यह हमारा अमेरिका नहीं है।' ट्रंप की पहली जीत को 'आर्थिक चिंता' और 'उपेक्षित रिपब्लिकन मतदाताओं' के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश की गई थी,

लेकिन अब इसे लेकर सिर्फ एक दुखद स्वीकारोक्ति है। जो लोग कभी सड़कों पर उतरने को तैयार थे, वे अब आपसी सहायता नेटवर्क बना रहे हैं, यह समझते हुए कि अब देश की कई संस्थाएं कमजोर, बेअसर या समाप्त हो जाएंगी।

अब, लगभग हर वह शक्ति जो ट्रंप को नियंत्रित कर सकती थी – चाहे वह पुनः चुनाव की संभावना हो या महाभियोग या आपराधिक दोषसिद्धि – समाप्त हो चुकी है। यह एक ऐसी सरकार होगी, जो किसी भी प्रकार के नैतिक बंधन, संस्थागत प्रतिबंधों या जवाबदेही से मुक्त होगी।

नवीनतम प्रशासन की अनिश्चित स्थिति

होगा। आज यह शरणार्थियों का निर्वासन और जलवायु संबंधी नियमों की कटौती है, तो कल कनाडा पर आक्रमण की धमकी हो सकती है। इसका अंतिम उद्देश्य लोगों को निराश करना है, ताकि वे कह दें, 'मैं तंग आ चुका हूँ, जब तक मेरी तनख्वाह समय पर आती रहे और मेरे अमेज़न के पैकेज पहुंचते रहें, मुझे परवाह नहीं कि ये नेता क्या कर रहे हैं।'

लेकिन यह झूठ होगा अगर हम यह दिखावा करें कि अज्ञानता का यह रवैया पिछले एक साल में सबसे भयावह तरीकों से नहीं बढ़ा है। कितनी बार एक लोकतांत्रिक प्रशासन के अंतर्गत, अमेरिकियों से कहा गया कि वे फिलिस्तीनी बच्चों के कटे हुए शरीर या जलते शरणार्थी शिविरों को न देखें?

बाइडेन प्रशासन की विरासत का विखंडन

इस डेमोक्रेटिक प्रशासन का संपूर्ण मूल्यांकन करने में लंबा समय लगेगा। लेकिन अभी भी यह स्पष्ट है कि बाइडेन की नीति और कार्रवाई के बीच एक बड़ा अंतर है। जलवायु परिवर्तन पर आपातकालीन भाषण और फिर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को बनाए रखना; शांति की बातें और फिर अनवरत युद्धों का वित्तपोषण।

डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यह चुनावी हार शायद उतनी मायने नहीं रखती जितनी दिखती है। पार्टी के बड़े नेताओं को पता है कि ट्रंप का प्रशासन सबसे कमजोर और असुरक्षित लोगों के खिलाफ सबसे अधिक निर्दयता दिखाएगा।

जलवायु परिवर्तन और असमानता

जनवरी में लॉस एंजेलिस के बड़े हिस्से जल गए। यह तबाही अविश्वसनीय थी, या शायद यह कहना गलत होगा। वास्तव में यह गहरी कल्पनीय है। चार साल पहले, पश्चिमी तट पर आई भयानक आग ने ओरेगन राज्य को तबाह कर दिया था। आज भी वहां नए घरों के बगल में खाली प्लॉट दिखते हैं, जहाँ सिर्फ चिमनी और पाइप बचे हैं।

कई लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक व्यापक समानता लाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। लॉस एंजेलिस के वे इलाके फिर से बन जाएंगे, क्योंकि यह इतिहास का सबसे अमीर देश है। जिनके पास साधन होंगे, वे फिर से अपने समुद्र तट के घरों को बना लेंगे, और बाकी कहीं और जाने को मजबूर होंगे।

यह जरूरी है कि हम आने वाली क्रूरता को दर्ज करें, ताकि हम संवेदनहीन न बनें।

ओमार एल अक्काद की आगामी पुस्तक का शीर्षक है - 'वन डे, एवरीवन विल हेव ऑलवेज बीन...'

डेमोक्रेट्स के लिए ट्रंप से मुकाबले का एक ही उपकरण है- संघीयता



रेनी लोथ

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति के पारंपरिक आदेश को इतना उलट दिया है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि जिन तारा-मणियों पर हम अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को मार्गदर्शन देने के लिए निर्भर करते हैं, वे आकाश से गिर गए हैं। इस उलट-फेर की दुनिया में, वे विचार और संघटनाएँ जो कभी एकदम नकारात्मक मानी जाती थीं, अब उपयोगी बन गई हैं। इसका एक उदाहरण: डेमोक्रेट्स और प्रगतिकारी कानूनी विद्वान संघीयता पर फिर से विचार कर रहे हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत कहता है कि कोई भी शक्तियाँ जो संघीय सरकार को स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं, वे राज्यों के पास होती हैं।

अधिकांश रिपब्लिकन संघीयता और इसके विकेंद्रीकृत सरकार के वादे का अनुसरण करते हैं; वास्तव में, फेडरलिस्ट सोसाइटी ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि ट्रंप ने -जो कि केवल अपनी शक्ति को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे- संघीयता का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किया, जब उन्होंने गर्भपात को अवैध बनाने का फैसला लिया। ('हमने इसे राज्यों के पास वापस ला दिया, और अब बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं,' उन्होंने 2024 के एक अभियान वीडियो में कहा।)

दशकों तक संघीयता लिबरल्स के लिए शाप साबित हुआ था, क्योंकि 'राज्य के अधिकार' को नस्लीय भेदभाव को सही ठहराने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल या समान-लिंग विवाह को रोकने, और कुछ साल पहले ही में कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण या संगरोध आदेशों को नकारने के लिए एक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब वॉशिंगटन खुद नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति शत्रु बन जाए, तो सरकार की अत्यधिक शक्ति को रोकने का एक तरीका हो सकता है। येल लॉ स्कूल की डीन हीदर गेरकेन ने तर्क किया है, 'संघीयता का कोई राजनीतिक रंग नहीं होता। यह प्रगतिकारी प्रतिरोध का स्रोत हो सकता है।'



यह एक मीठा विडंबना है कि एक ऐसा सिद्धांत, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में प्रगतिकारी बदलाव को धीमा करने के लिए किया जाता था, अब प्रगतिकारी नेताओं के हाथों में एक उपकरण बन गया है, जो ट्रंप के एजेंडे को विफल करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में, गवर्नर गैविन न्यूजॉम ने

देश के सबसे बड़े और समृद्ध राज्य को 'ट्रंप-प्रूफ' बनाने के लिए \$50 मिलियन का एक वैधानिक पैकेज पेश किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अप्रवासियों को निर्वासन से बचाना है, जो ट्रंप ने अपनी उद्घाटन भाषण में 'एक स्तर पर ऐसा करने का वादा किया था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।' इलिनॉयस में, गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने भी अपने राज्य की 'संकुचारी' स्थिति को बनाए रखने का वादा किया है, जो अधिकांश मामलों में स्थानीय कानून प्रवर्तन को संघीय अप्रवासन अधिकारियों के साथ सहयोग करने से रोकता है। 'तुम मेरे लोगों के पास आओ, तो तुम मुझसे होकर आओ,' प्रिट्जकर ने चेतावनी दी — यह क्रसमें जल्द ही परखी जाएगी।

राज्य वितरण पर और चुनौतियों का सामना किया जा सके। अटॉर्नी जनरल एंड्रिया कैपबेल अब उन क्षेत्रों में अपनी टीम को मजबूत कर रही हैं, जो ट्रंप के निशाने पर हैं, जैसे LGBTQ अधिकार और बंदूक हिंसा संरक्षण।

ट्रंप के पहले कार्यकाल की तरह, डेमोक्रेटिक राज्य उनके व्यापक आदेशों को रोकने या कम से कम उन्हें देर से लागू करने के लिए मुकदमे तैयार कर रहे हैं। ट्रंप की आदत है राज्यों और यहां तक कि कांग्रेस को भी बिना किसी दया के मात देना, जो पहले ही एक संवैधानिक संकट की ओर इशारा कर रहा है। अपने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद, 18 अटॉर्नी जनरल ने मैसाचुसेट्स में मुकदमा दायर किया था ताकि ट्रंप के प्रयासों को रोका जा सके, जो अमेरिकी जन्मे अप्रवासियों के बच्चों के लिए नागरिकता समाप्त करना चाहते थे — जो संविधान के 14वें संशोधन के तहत एक गारंटी है। कैपबेल इस मुकदमे में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में ग्लोब से एक साक्षात्कार में कहा, 'हमारे पास किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए उपकरण हैं, और हम इन्हें इस्तेमाल करने से नहीं डरते।'

लेकिन यह सिर्फ ट्रंप के एजेंडे का विरोध करने तक सीमित नहीं है। ब्लू स्टेट्स संघीयता के झंडे तले सकारात्मक नीतियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं: न्यूनतम वेतन में वृद्धि, प्रगतिशील कर सुधार, स्वतंत्र प्रेस के लिए सुरक्षा, पर्यावरण मानक, और मादक पदार्थों की वैधीकरण। जैसा कि न्यायमूर्ति लुई ब्रांडीस ने लगभग एक सदी पहले लिखा था, संघीय प्रणाली 'एक साहसी राज्य' को 'नवीन सामाजिक और आर्थिक प्रयोगों' को आजमाने की अनुमति देती है।

वास्तव में, एक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का मामला, जिस पर प्रारंभ में लिबरल्स ने दुख व्यक्त किया था, अब प्रगतिशील राज्य कार्यवाहियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जून में, कोर्ट ने तथाकथित चेरॉन निर्णय को खारिज कर दिया, जो 1980 के दशक से अदालतों को निर्देशित करता था कि वे संघीय एजेंसियों के पक्ष में खड़े हों, जब कांग्रेस से स्पष्ट दिशा नहीं मिलती (उदाहरण के लिए, जब पर्यावरण संरक्षण एजेंसी पर्यावरणीय नियमों को लागू करने का प्रयास करती है)। जून के निर्णय का तर्क — कि संघीय सरकार राज्यों को अस्पष्ट संघीय नियमों को लागू करने के लिए 'आदेश' नहीं दे सकती — कार्यकारी शाखा, यानी ट्रंप, को कम महत्त्व देता है।

संविधान विशेषज्ञ अक्सर यह नोट करते हैं कि संघीयता अप्रभावी हो सकती है और विभाजित सरकार का परिणाम देती है। लेकिन इन अजीब दिनों में, शायद यह समय है विभाजन को अपनाने का और इसे उन राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक अधिकारों, पर्यावरण और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उपयोग करने का, जहां ये खजाने अभी भी मूल्यवान हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रो.वी. वेड के फैसले को पलटने के बाद, मैसाचुसेट्स ने यहां प्रजनन अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए। इसके अलावा, गवर्नर मौराह हीली ने 2023 में गर्भपात की गोली मिफेप्रिस्टोन का भंडारण किया, ताकि दवा के अंतर-



चंद्र प्रकाश साल्वे

ट्रम्प 2.0

'क्वाड' की भूमिका



ट्रंप प्रशासन 2.0 की पहली क्वाड विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद एक फोटो सेशन में जापान के विदेशमंत्री ताकेशी इवाया, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो और ऑस्ट्रेलिया की विदेशमंत्री पेनी वॉंग।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति, सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीतियाँ समय के साथ विकसित होती हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आए हैं, उनमें ट्रंप प्रशासन के निर्णयों का महत्वपूर्ण स्थान है। खासतौर पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच 'क्वाड' (Quad) पहल को लेकर यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

जब ट्रंप प्रशासन के मार्को रुबियो ने अपनी विदेश मंत्री के रूप में पहली बैठक की, तो इस बैठक ने कई पहलुओं को उजागर किया, जिनसे यह साफ था कि 'क्वाड' को लेकर ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण चीन की बढ़ती शक्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण था। इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में, चार देशों ने समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय विकास की दिशा में

एकजुट होने का संकेत दिया, साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया।

क्वाड का उद्देश्य और इसका विकास

क्वाड का गठन 2007 में हुआ था, जब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भारतीय महासागर में 2004 के भूकंप और सुनामी के बाद मिलकर राहत कार्य किए थे। तब से यह समूह एक बहुपक्षीय मंच के रूप में विकसित हुआ, जिसमें विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे आपातकालीन सहायता, जलवायु परिवर्तन, और समुद्री सुरक्षा पर सहकार्य की आवश्यकता महसूस की गई। हालांकि, क्षेत्रीय सुरक्षा, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत, इस पहल का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस पहल को लेकर अपनी स्पष्ट राय दी है। उनका मानना है कि भारत के लिए क्वाड में सहयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने इस बारे में कई बार यह कहा कि भारत का हित इस बात में है कि वह न केवल एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बने, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक सहयोगी के रूप में भी उभरे।



चीन के संदर्भ में भारत और अमेरिका का सहयोग

क्वाड का उद्देश्य चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करना है, खासकर दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे रणनीतिक स्थानों पर। ट्रंप प्रशासन के दौरान, अमेरिका ने भारत को एक आवश्यक सहयोगी के रूप में देखा। एस. जयशंकर ने इस पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत को वैश्विक ताकतों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनानी चाहिए, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके।

ट्रंप ने चीन के प्रति अपनी कड़ी नीति को लेकर काफी स्पष्टता दिखाई थी। उन्होंने इसे 'आधिकारिक विरोधी' और 'खतरनाक' बताया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जो पहले चीन के प्रति बेहद आक्रामक रुख रखते थे, ने ट्रंप के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए चीन को एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। उन्होंने चीन के मानवाधिकार उल्लंघन और उसके क्षेत्रीय दावे को लेकर कई बार कड़े बयान दिए।

भारत ने भी चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध किया है,

विशेषकर उसकी सीमा विवादों को लेकर। भारत-चीन सीमा पर तनाव और चीन का पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। इस संदर्भ में, भारत और अमेरिका का सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर उस स्थिति में जब दोनों देशों को अपने-अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी हो।

'अमेरिका फर्स्ट' नीति और भारत

ट्रंप की 'America First' नीति के तहत, अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना था। यह नीति विदेशों में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने के लिए थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कई देशों के साथ संबंधों में असंतोष भी देखा गया। भारत के लिए, यह एक चुनौती थी, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में असंतुलन था और ट्रंप प्रशासन ने बार-बार व्यापार शुल्कों में वृद्धि की धमकी दी थी।

हालांकि, एस. जयशंकर ने इस स्थिति को संतुलित रूप से संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत बनाए रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अमेरिका के साथ रिश्तों को बढ़ाए और साथ ही अपनी

स्वतंत्र नीति बनाए रखे।

भारत ने अमेरिका के 'America First' दृष्टिकोण को समझते हुए, न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी अमेरिका के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य केवल चीन को लेकर अमेरिका के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करना नहीं है, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करना है।

क्वाड और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा

क्वाड का गठन चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इस समूह के चार सदस्य देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे किसी भी एकतरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिति को बलपूर्वक बदलने का प्रयास करती हो। यह बयान चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था।

चीन ने क्वाड को लेकर कई बार यह आरोप लगाया कि यह एक

'एशियाई नाटो' बनाने का प्रयास है, जो कि एक गलतफहमी है। क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि यह देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एस. जयशंकर ने इस पर अपनी राय दी कि भारत के लिए क्वाड का उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, न कि किसी प्रकार के सैन्य संघर्ष को बढ़ावा देना।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते कूटनीतिक संबंध, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन के तहत, क्वाड और दक्षिण एशिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केवल भारत-अमेरिका के संबंधों पर बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है, जो दक्षिण एशिया के सुरक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक समीकरणों में केंद्रीय स्थान रखते हैं।

क्वाड और पाकिस्तान-बांग्लादेश का संदर्भ

हालांकि, क्वाड के तहत सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य मुख्य रूप से चीन को चुनौती देना है, लेकिन इसका प्रभाव पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर भी पड़ता है, जो दक्षिण एशिया के राजनीतिक और सुरक्षा संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान की स्थिति हमेशा से क्वाड के दृष्टिकोण से विवादित रही है। पाकिस्तान, जो चीन का करीबी सहयोगी है, उसने कई बार यह आरोप लगाया है कि क्वाड का उद्देश्य चीन को घेरना और उसके खिलाफ एक नकारात्मक कूटनीतिक माहौल बनाना है। पाकिस्तान के लिए, यह सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति की एक चुनौती है, क्योंकि क्वाड की सैन्य और रणनीतिक रणनीतियाँ सीधे तौर पर पाकिस्तान की सुरक्षा नीति से टकराती हैं।

पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध कभी सहज नहीं रहे हैं। पिछले ट्रंप प्रशासन के दौरान, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया था, खासकर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। भारत के साथ अमेरिका का बढ़ता सहयोग पाकिस्तान को चिंता में डालता था, क्योंकि दोनों देशों का संबंध चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को चुनौती देता है।

बांग्लादेश, जो भारत का एक प्रमुख पड़ोसी और मित्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन बीते छह महीने के दौरान यह मैत्रीपूर्ण संबंध लगभग खत्म हो गये हैं और तनावपूर्ण स्थिति बनी है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति और इसके भीतर चल रही इस्लामिक कट्टरपंथी

गतिविधियां न केवल बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि भारत के साथ संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से आर्थिक विकास प्रक्रियाएँ, जो भारत-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जापान के साथ सहयोग से बांग्लादेश में चल रही हैं, वह गहरे स्तर पर प्रभावित हुई हैं। बांग्लादेश ने चीन के साथ अपनी घनिष्ठ व्यापारिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं, जैसे कि चीन द्वारा बांग्लादेश में निवेश करना और बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बांग्लादेश को शामिल करना। यह भारतीय हितों के खिलाफ है। बांग्लादेश का रुख अब तक क्वाड के प्रति तटस्थ रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्तों का असर बांग्लादेश की कूटनीतिक नीति पर भी हो सकता है। बांग्लादेश के लिए,

भारत ने हमेशा पाकिस्तान से आतंकवाद और सीमा सुरक्षा मुद्दों पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी है, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा है।

एक ओर चीन के साथ संबंधों का महत्व है, वहीं दूसरी ओर भारत और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते भी उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। बांग्लादेश पर देश में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली के लिए वर्तमान अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनूस पर दबाव बनेगा। ट्रंप और यूनूस के बीच के संबंधों की तल्लियाँ मोहम्मद यूनूस के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली हो सकती हैं।

पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका और भारत की नीति

पाकिस्तान के साथ भारत और अमेरिका दोनों का रुख काफी जटिल रहा है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान से आतंकवाद और सीमा सुरक्षा मुद्दों पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी है, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा है। ट्रंप प्रशासन के तहत, अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह के रूप में लगातार आलोचना की और पाकिस्तान से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की उम्मीद की। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर सवाल उठाए, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए अमेरिकी सहयोग में गिरावट आई।

भारत ने अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में अपने संबंधों को बढ़ाने का फायदा उठाया और पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अकेला किया। भारत की कूटनीति में यह साफ था कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय चुनौती का मुकाबला करने के लिए उसे अमेरिका की मदद की आवश्यकता होगी।

डोनाल्ड ट्रंप के 2025 में राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ लेने के बाद, भारत और अमेरिका के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने इन रिश्तों को एक नई दिशा दी, जिससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, ऊर्जा, इमिग्रेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहरा असर पड़ा। हम इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह विश्लेषण करेंगे कि ट्रंप के प्रशासन में भारत-अमेरिका संबंध किस दिशा में बढ़े हैं।

गगन बत्रा

ट्रम्प 2.0

भारत-अमेरिका संबंधों में नई दिशा

ट्रंप के प्रशासन के तहत, भारत ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अपनी बाजार पहुंच को सरल बनाने के लिए कदम उठाए। इस बदलाव के मुख्य कारणों में व्यापार असंतुलन को संबोधित करना और 'प्रतिस्पर्धी कर' के खतरों से बचना था। ट्रंप ने व्यापार असंतुलन की समस्या को उठाया था, और अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर शुल्क में कटौती का समर्थन किया।

भारत ने विशेष रूप से कृषि उत्पादों, उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों और लकड़ी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क में कटौती करने की योजना बनाई। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश को आसान बना दिया गया। उदाहरण के लिए, ट्रंप ने मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियों से बात की और भारत में लकड़ी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने की बात की। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान में सुधार हुआ।

यह कदम भारत के लिए भी लाभकारी था क्योंकि इससे उसे अमेरिकी उत्पादों की बढ़ी हुई आपूर्ति मिल रही थी और व्यापार असंतुलन में कमी आई। हालांकि, इन व्यापारिक सुधारों के बावजूद कुछ क्षेत्रों में असंतुलन बना रहा। ट्रंप प्रशासन की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी, और इसके तहत कई क्षेत्रों में शुल्क में कटौती की गई, लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए अपने व्यापारिक घाटे को कम करना एक प्राथमिकता बनी रही।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

ट्रंप के ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने के फैसले ने भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी नई साझेदारी का रास्ता खोला। ट्रंप प्रशासन के तहत, भारत ने



अमेरिकी तेल और गैस की खरीद बढ़ाने की योजना बनाई। अमेरिका में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ, भारत को अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों के लिए एक स्थिर आपूर्ति मिल रही थी, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक साबित हुआ।

भारत की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता आयात से पूरी होती है, और इस संदर्भ में अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की बढ़ती आपूर्ति से भारत को लाभ हुआ। ट्रंप प्रशासन के तहत, भारत ने अमेरिका से अधिक कच्चा तेल और गैस आयात करने के अवसरों को बढ़ाया। इसके साथ ही, भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश का एक नया रास्ता खुला।

इस सहयोग के परिणामस्वरूप, ऊर्जा व्यापार में वृद्धि हुई और भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक नया मार्गदर्शन मिला। ऊर्जा संबंधों के क्षेत्र में यह सहयोग ट्रंप प्रशासन के तहत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला।

इमिग्रेशन और H-1B वीजा

इमिग्रेशन और वीजा नीतियों में भी ट्रंप प्रशासन का भारत के साथ विशेष संबंध था। ट्रंप ने अमेरिका में अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए कड़ी नीतियां अपनाईं। भारत ने इस संदर्भ में ट्रंप प्रशासन के साथ सहयोग बढ़ाया, विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों की पहचान और प्रत्यावर्तन को लेकर जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे।

H-1B वीजा, जो भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण था, पर भी ट्रंप प्रशासन के तहत कई बदलाव किए गए। ट्रंप के दृष्टिकोण के तहत, यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि ट्रंप ने इन वीजा कार्यक्रमों को अधिक कड़ा करने की योजना बनाई। हालांकि, भारत ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वीजा

नीति पर नियमित बातचीत की, जिससे वीजा की प्रक्रिया में सुधार हो सकता था, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के बीच लंबे समय तक बातचीत चलती रही।

चीन के खिलाफ संयुक्त रणनीति

ट्रंप प्रशासन ने चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए भारत के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई। चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका ने 'क्वाड' देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। मार्को रूबियो ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई।

क्वाड देशों के बीच सहयोग से भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नई गहराई आई। ट्रंप ने क्वाड देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे भारत के लिए भी चीन के खिलाफ रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना महत्वपूर्ण हो गया। चीन के क्षेत्रीय दबाव को चुनौती देने के लिए दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक हितों ने उन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। यह साझेदारी भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अहम साबित हो सकती है, खासकर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में।

ट्रंप प्रशासन के तहत भारत-अमेरिका संबंधों में व्यापार, ऊर्जा, इमिग्रेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के बावजूद, भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों को समझते हुए सहयोग बढ़ाया। दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ते और साझा रणनीतिक हितों ने इन संबंधों को और मजबूत किया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ बनी रहीं, जैसे H-1B वीजा और व्यापार असंतुलन, लेकिन समग्र रूप से, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में सकारात्मक बदलाव आया।



ट्रम्प 2.0

अफगान शरणार्थियों की टूटी उम्मीदें

कल्ट करंट ब्यूरो

अफगानिस्तान में दशकों से चले आ रहे संघर्ष और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के कारण कई अफगानों को अपने देश से पलायन करना पड़ा। उनमें से कई लोगों ने अमेरिका में पुनर्वास की उम्मीद से अपने आवेदन जमा किए और वर्षों तक इस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार किया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अप्रत्याशित रूप से वीजा प्रक्रिया को रोक दिया, तो इन शरणार्थियों की आशाएं टूट गईं। इस निर्णय से पाकिस्तान में अस्थायी रूप से रह रहे कई अफगान शरणार्थियों के जीवन में अनिश्चितता और निराशा का माहौल पैदा हो गया है।

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले अफगान छात्र अपनी अमेरिकी पुनर्वास प्रक्रिया के रुकने की खबर सुनकर स्तब्ध हैं। पहले जो छात्र उत्साहित और आशान्वित थे, वे अब निराशा और गहरे अवसाद में डूबे हुए हैं। 20 वर्षीय शिक्षक सैयद हसीब उल्लाह, जो खुद अमेरिका में पुनर्वास के लिए आवेदन कर चुके हैं, कहते हैं, 'यह हमारे लिए एक भयावह क्षण था। हम तीन साल से इंतजार कर रहे हैं, और अब कोई उम्मीद नहीं बची है।' इन छात्रों और शिक्षकों ने अपने भविष्य की कई योजनाएं बनाई थीं, जो अब अधर में लटक गई हैं।

शरणार्थियों की कठिनाइयाँ

इस्लामाबाद के एक इंग्लिश स्कूल की छात्रा, जो अमेरिका में पढ़ाई करने की उम्मीद कर रही थी, समाचार सुनते ही रो पड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के कारण उसे अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी थी, और अब अमेरिकी वीजा प्रक्रिया के रुकने से उसकी उच्च शिक्षा की उम्मीदें भी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान में इन शरणार्थियों के लिए काम करने या औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की कोई वैध व्यवस्था नहीं है, और अमेरिकी पुनर्वास ही उनका एकमात्र सहारा था।

सैकड़ों अफगानों की निराशा

पाकिस्तान में 10,000 से 15,000 अफगान शरणार्थी विशेष आब्रजन वीजा (SIV) या शरणार्थी पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से कई लोग तालिबान के अत्याचारों से बचने के लिए यहां आए थे, लेकिन अब वे भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर असहाय महसूस कर रहे हैं। यह संकट 2023 में पाकिस्तान द्वारा अफगानों को निर्वासित करने के बाद और गंभीर हो गया, जब इस देश ने भी अपने आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों के चलते इन्हें स्वीकारने में असमर्थता जताई। इन शरणार्थियों में ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे अमेरिकी सैन्यकर्मियों के परिवार वाले और अमेरिकी परियोजनाओं में काम करने वाले विकास कार्यकर्ता।

विश्वासघात की भावना

57 वर्षीय फातिमा, जो दशकों तक महिलाओं के अधिकारों और विकास के लिए काम करती रहीं, अब अमेरिका की वीजा प्रक्रिया के अचानक रुकने से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'आपने हमें उस समय समर्थन दिया और हमें आगे बढ़ाया, इसलिए हमने आपके साथ काम किया। अब आप



हमें ऐसे समय में पीछे छोड़ रहे हैं, जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है।' फातिमा अपनी 15 वर्षीय बेटी की शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं, जो पिछले कई सालों से स्कूल से बाहर है। इसके अलावा, वह चाहती है कि उनकी 22 वर्षीय बेटी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सके।

संदेश का असर

ट्रंप के इस आदेश ने न केवल शरणार्थियों के मनोबल पर गहरा आघात किया है, बल्कि अमेरिकी नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और विकास परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद, अब उन लोगों की मदद करने में असमर्थता जताई जा रही है, जिन्होंने अमेरिकी बलों के साथ मिलकर काम किया और उनके हितों की रक्षा की। हसीब उल्लाह ने कहा, 'हमने आपकी मदद की, और अब हमें आपसे मदद की उम्मीद थी।'

अफगान शरणार्थियों की इस त्रासदी ने वैश्विक राजनीति में मानवाधिकार और नैतिक जिम्मेदारियों के सवालों को फिर से सामने ला दिया है। पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थी न केवल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, बल्कि अब वे अपने सुरक्षित भविष्य की आशाओं को भी खोते जा रहे हैं। अमेरिकी नीतियों के तहत उन्हें जिस सुरक्षा और पुनर्वास का आश्वासन दिया गया था, वह अब उनके लिए एक अधूरा सपना बन गया है।

ईरान-रूस की नई साझेदारी वैश्विक प्रभाव व संभावित परिणाम



ईरान और रूस के बीच उभरती हुई नई साझेदारी वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करती है। इन दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग न केवल पश्चिमी शक्तियों की चिंताओं को बढ़ा रहा है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, और क्षेत्रीय सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेझेइकयन की मास्को यात्रा के दौरान जनवरी 17 को औपचारिक रूप से की जाने वाली 'समग्र रणनीतिक साझेदारी समझौते' की पुष्टि इस गठबंधन को और मजबूत करेगी।

ईरान-रूस साझेदारी के मुख्य स्तंभों में परिवहन, ऊर्जा, रक्षा, और क्षेत्रीय सुरक्षा शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की जड़ें केवल आर्थिक लेन-देन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और पश्चिमी प्रभाव को रोकने के साझा लक्ष्यों तक फैली हुई हैं।

1. परिवहन सहयोग: उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा

इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (NSTC) है, जो ईरान, रूस और अन्य क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच व्यापार को सुगम बनाएगा। यह बुनियादी ढांचा परियोजना पश्चिमी प्रतिबंधों का मुकाबला करने में एक मजबूत कदम है, क्योंकि इससे इन दोनों देशों को अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और पारस्परिक लाभ सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा।

यह गलियारा न केवल ईरान-रूस व्यापार को मजबूत करेगा, बल्कि यूरोप, मध्य एशिया, और चीन-भारत जैसे बाजारों तक पहुंच बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे दोनों देशों को वैश्विक व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी मजबूत

होगी।

2. ऊर्जा सहयोग: पश्चिमी बाजारों से स्वतंत्रता

ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान-रूस सहयोग इस साझेदारी की रीढ़ है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने दोनों देशों की ऊर्जा उद्योग को सीमित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वे वैकल्पिक मार्गों की तलाश में हैं। रूस, जो विश्व में सबसे बड़े तेल और गैस संसाधनों का मालिक है, ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसके तहत खोज, ड्रिलिंग और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे कदम शामिल हैं।

नई समझौते के तहत कई रूसी कंपनियां ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश करेंगी, जिससे ईरान की ऊर्जा क्षमताओं को उन्नत और विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा, एशिया में बढ़ती ऊर्जा मांग के संदर्भ में यह सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

3. सैन्य सहयोग: क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार

ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग ने इन दोनों देशों को क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभारा है। ईरान द्वारा रूस को ड्रोन जैसी उन्नत सैन्य तकनीकों की आपूर्ति ने न केवल इन दोनों देशों को सैन्य रूप से मजबूत किया है, बल्कि इसे पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप

के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

रूस की यूक्रेन में कम लागत, उच्च क्षमता वाले शहीद-136 ड्रोन (जो रूस में 'गेरान-2' के नाम से जाने जाते हैं) की बढ़ती उपयोगिता ने मास्को को न केवल यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाने का साधन दिया है, बल्कि यह तकनीक पूर्वी यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भी फैलने की संभावना रखती है।

4. भविष्य की चुनौतियां और बाधाएं

हालांकि यह साझेदारी भविष्य में गहरे सहयोग का वादा करती है, यह कई चुनौतियों का भी सामना कर रही है। ईरान और रूस दोनों देशों के आंतरिक राजनीतिक मतभेद, आर्थिक कठिनाइयाँ, और भू-राजनीतिक एजेंडाओं में विभाजन इस साझेदारी की पूरी क्षमता को बाधित कर सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, रूस ने पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास किया है, जिससे ईरान के साथ तनाव उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए, 2000 के दशक में जब रूस ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का समर्थन किया था, तब संबंधों में कमी आई थी। इसके अलावा, रूस का एस-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति में देरी ने भी दोनों देशों के बीच विश्वास को कम किया था।

5. आर्थिक संकट और भविष्य की चुनौतियाँ

आर्थिक दृष्टि से, प्रतिबंधों ने रूस और ईरान दोनों की ऊर्जा भंडारों का पूरी तरह से लाभ उठाने की क्षमता को प्रभावित किया है। ईरान की अर्थव्यवस्था की अत्यधिक निर्भरता तेल निर्यात पर

है, जो वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण अस्थिर हो जाती है। इसके साथ ही, ईरान को लगभग 35% मुद्रास्फीति दर का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके आर्थिक विकास को रोकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों को अपने आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों को सावधानीपूर्वक नेविगेट करने की आवश्यकता है ताकि मौजूदा कमजोरियों को बढ़ने से रोका जा सके।

6. वैश्विक प्रभाव और भू-राजनीतिक स्थिति

इस साझेदारी के चलते वैश्विक संतुलन में भी बदलाव आने की संभावना है। ईरान-रूस गठबंधन पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, इन दोनों देशों ने खुद को नए व्यापार मार्गों और एशियाई बाजारों में समेकित किया है।

ऊर्जा, परिवहन और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में इस गठबंधन की प्रगति न केवल मध्य पूर्व में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुरक्षा और आर्थिक रणनीतियों को पुनः परिभाषित कर सकती है।

यह साझेदारी उन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को चुनौती देती है जहां पश्चिमी शक्तियाँ लंबे समय से प्रभुत्व बनाए रख रही थीं। जैसे-जैसे ईरान और रूस अपने सैन्य और आर्थिक सहयोग को गहरा करते हैं, पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ उनकी स्थिति और मजबूत होती जाएगी।

हालांकि, भविष्य में इस गठबंधन को बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से अमेरिका, रूस और चीन के बीच बदलती शक्ति गतिशीलता के संदर्भ में।

ईरान और रूस के बीच उभरती हुई साझेदारी वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देती है। परिवहन, ऊर्जा, और सैन्य सहयोग के क्षेत्रों में मजबूत गठबंधन न केवल पश्चिमी प्रतिबंधों का मुकाबला करेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी एक नई धुरी की स्थापना करेगा।

हालांकि, इस साझेदारी के सामने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियाँ हैं, जिनसे दोनों देशों को निपटना होगा। अगर वे अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएँ और आंतरिक बाधाओं को पार कर सकें, तो यह गठबंधन आने वाले वर्षों में वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।

'नई ईरान-रूस साझेदारी का विश्व के लिए क्या अर्थ होगा?' शीर्षक से मूल आलेख, जो द मास्को टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, के आधार पर क्यूरेट किया गया यह संस्करण अद्यतन जानकारी के साथ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

महाकुंभ भगदड़ में 30 की मौत



प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन तड़के 2 बजे के आसपास मची भगदड़ ने एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने के साथ-साथ 30 से अधिक लोगों की जान जाने की भी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यह भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन हुई, जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक है। अनुमान था कि इस दिन लगभग 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। संगम में डुबकी लगाने की मान्यता के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर एकत्रित हो गए। इस बार ग्रहों का एक विशेष योग भी था, जिसके कारण श्रद्धालुओं में संगम में डुबकी लगाने का विशेष उत्साह था। इस घटना ने महाकुंभ में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्वीकार किया है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई लोगों की जानें गई हैं। वहीं दूसरी तरफ, प्रशासन की ओर से सही जानकारी न दिए जाने से लोगों में भ्रम और चिंता बढ़ गई है।

2025

महाकुंभ

संस्कृति के संगम में अध्यात्म की दिव्यता



जलज श्रीवास्तव

भारत की पावन धरा पर स्थित प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र धाराएं एकाकार होती हैं, वह स्थान मात्र भौगोलिक मिलन नहीं, बल्कि अध्यात्म और संस्कृति का महासंगम है। यह वह भूमि है, जो सहस्राब्दियों से साधकों, ऋषियों और संतों की साधनाओं का केंद्र रही है। कुंभ का आयोजन इस संगम पर महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समग्र भारतीय संस्कृति का उत्सव है, जो हमें हमारी सभ्यता की गहराईयों से जोड़ता है।

कुंभ मेले की परंपरा सहस्राब्दियों पुरानी है, जिसे पौराणिक कथा से भी जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ, तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर चार स्थानों पर गिरीं—प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, और नासिक। इन चारों स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन हर बारह वर्ष में होता है। किंतु प्रयागराज का महाकुंभ विशेष है, क्योंकि यह केवल बारह वर्षों का नहीं, बल्कि एक संपूर्ण चक्र का प्रतीक होता है, जो हर 144 वर्षों में एक बार आता है। यह वह समय होता है जब असंख्य श्रद्धालु, साधु-संत और योगी संगम तट पर इकट्ठे होते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस पवित्र स्थल पर स्नान करते हैं और स्वयं को आध्यात्मिक यात्रा में लीन कर देते हैं।

इस वर्ष का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। यह मात्र संख्या का खेल नहीं, यह उस आस्था का प्रतीक है जो भारत के हर कोने से लेकर विश्व के कोने-कोने तक फैली हुई है। हर श्रद्धालु, चाहे वह गरीब हो या धनी, यहां आकर संगम के जल में डुबकी लगाकर स्वयं को शुद्ध करता है, अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है और एक नवीन जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। यह केवल धार्मिक आस्था का ही पर्व नहीं है, यह समरसता और मानवता की विजय का प्रतीक भी है। जब संगम की माटी पर लाखों-करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, तो वे केवल स्नान नहीं करते, वे उस अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो सहस्राब्दियों से इस धरा पर संचित है। कुंभ का यह संगम मानवता के लिए अमृत के समान है, जो जीवन को शुद्ध करता है और आत्मा को मोक्ष की ओर

अग्रसर करता है।

कल्पवास: तप का यज्ञ

कुंभ के समय संगम तट पर साधु-संतों और श्रद्धालुओं का विशेष आकर्षण होता है 'कल्पवास'। यह केवल स्नान करने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की एक संपूर्ण साधना है। कल्पवास वह समय है जब श्रद्धालु एक माह तक संगम तट पर निवास करते हैं, अपनी दैनिक जीवन की साधारणता को छोड़कर तपस्वियों की भांति जीवन जीते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तीन बार पवित्र जल में स्नान करना, और एक समय भोजन करना, ये सभी क्रियाएं कल्पवास के नियम हैं। यह तपस्वी जीवन केवल बाहरी अनुशासन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। जब व्यक्ति संगम के शीतल जल में स्नान करता है, तो वह केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर की अपवित्रताओं से भी मुक्ति प्राप्त करता है। कल्पवास का यह यज्ञ उस आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है, जो हमें भौतिकता से दूर करके आत्मा के सत्य स्वरूप की ओर ले जाता है।

समरसता और एकता का संगम

कुंभ मेला केवल धार्मिक उत्सव नहीं, यह सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यहां कोई जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। लाखों श्रद्धालु चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हों, संगम के पवित्र जल में एक साथ स्नान करते हैं और एक समान अनुभव प्राप्त करते हैं।

यह मेला मानवता की उस विशाल एकता का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यहां आकर हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। कुंभ का यह अद्वितीय आयोजन उस सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, जो सहस्राब्दियों से भारतीय समाज को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधती आई है।

शाही स्नान व अखाड़े

कुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान और अखाड़ों की पारंपरिक शोभायात्रा इस मेले की भव्यता को और भी अद्भुत

बनाते हैं। नागा साधुओं की विशाल टोलियां, हाथियों पर सवार साधु-संत और पारंपरिक वेशभूषा में आभूषणों से सुसज्जित साधु जब संगम की ओर बढ़ते हैं, तो यह दृश्य किसी दिव्य लोक की यात्रा के समान होता है।

यह शोभायात्रा केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है, जो हमें हमारे सनातन धर्म की गहराईयों से जोड़ती है। अखाड़ों के नागा साधु अपनी तपस्वी परंपरा को धारण करते हुए कुंभ में भाग लेते हैं, और यह संदेश देते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति का समर्पण किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

वैश्विक आकर्षण: महाकुंभ का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व

आज का महाकुंभ केवल भारतीयों का नहीं रहा, यह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्वितीय आयोजन का हिस्सा बनने आते हैं। विदेशी श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने आते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गहन अध्ययन भी करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में महाकुंभ का आकर्षण इस्लामिक देशों में भी बढ़ा है। पाकिस्तान, कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों से लोग महाकुंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक धरोहर आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है।

धर्म संसद: सनातन शक्ति का जागरण

महाकुंभ केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, यह राष्ट्र के भविष्य को दिशा देने वाला भी है। यहां होने वाली धर्म संसदें और सामाजिक संगठन एकत्र होकर राष्ट्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत भी कुंभ के इसी धर्म संसद से हुई थी, और आज यह आंदोलन राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका है।

2025 के महाकुंभ में भी सनातन धर्म की शक्ति का जागरण हो रहा है। यह आयोजन केवल अतीत की धरोहर को संजोने का नहीं, बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का भी संदेश दे रहा है।

अध्यात्म की महायात्रा

महाकुंभ में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनता है। संगम में स्नान करने के बाद जब वह अपने घर लौटता है, तो वह केवल बाहरी शुद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि भी साथ लेकर जाता है। कुंभ का यह आयोजन एक ऐसा दर्पण है, जो हमें हमारे जीवन के सत्य और उद्देश्य से परिचित कराता है।

संगम हमें यह सिखाती है कि जीवन के सभी कष्टों और संघर्षों का समाधान अध्यात्म और आस्था में निहित है। महाकुंभ का यह अनंत पर्व हमारे भीतर की चेतना को जाग्रत करता है, और हमें उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। महाकुंभ का अंतिम स्नान उस परमात्मा के साथ एकाकार होने का प्रतीक है, जो हमें हमारी अस्थाई देह से परे ले जाता है।

सियासत के बारे में एक आम धारणा है कि यहाँ स्वहित सबसे बड़ा धर्म है। मतलब साफ है कि सियासत में कोई किसी का स्थायी न दोस्त माना जाता है और न दुश्मन। यहाँ किसी भी तरह की संवेदनशीलता का भी कोई स्थान नहीं है। यहाँ सब कुछ निर्भर करता है स्वार्थ सिद्धि पर। अगर आपका जिससे हित सधता है वो आपका सबसे अधिक सगा माना जाता है। यही वजह है कि अब समाज की हर गतिविधियों में सियासी दखलंदाजी बढ़ रही है। ऐसे में भला महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन कैसे अछूता रह पाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि सर्वोच्च स्थान धार्मिक आस्था का होता है लिहाजा यहाँ की सियासत का स्वरूप प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ के सभी धार्मिक गतिविधियों में सियासी नफा-नुकसान को तलाशा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के कैबिनेट की पूरी टीम प्रयागराज में गंगा-यमुना सहित अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में डुबकी लगाती है और संगम तट पर कैबिनेट की बैठक करती है तो विपक्षी इसे सियासत करार देते हैं। संभव है कि विपक्ष का यह कयास पक्ष-विपक्ष की सियासी दाँव-पेंच के चलते बहुत पारिभाषित न हो पाए। लेकिन जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में लगभग दो लाख करोड़ के राजस्व मिलने की उम्मीद जताई है। वह बेवजह की बयानबाजी मात्र नहीं है बल्कि एक सोची-समझी दूरदर्शी गणित के फार्मूला माफिक है। माघ मेला हो, अर्ध कुम्भ हो, कुम्भ हो या महाकुंभ सभी को सकुशल सम्पन्न कराने कि जिम्मेदारी संबंधित प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की होती है। लेकिन नाथ संप्रदाय के कट्टर साधक योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रयागराज में आयोजित लगभग सभी कुम्भ के आयोजनों को ऐसा स्वरूप दिया कि साल दर साल यह धार्मिक आयोजन दिव्यता और भव्यता की मिसाल बनते जा रहे हैं। 2019 का कुम्भ हो या इस बार 2025 का महाकुंभ, सभी



शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव



सियासत और प्रयाग का महाकुंभ

ने बेहतर व्यवस्था का रिकार्ड बनाया है। सदियों से आयोजित होता आ रहा यह आयोजन आज भारतीय समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जागरण का प्रतीक बन गया है। इसे भी राजनीतिक जागरण का ही प्रतिफल माना जाएगा कि कभी सीमित संसाधनों के बीच गंगा-यमुना के तट पर खुले आसमान तले कल्पवासी सामान्य से टेंट में रहकर भगवतभजन किया करते थे। जबकि आज लाखों-लाख रुपये टेंट निवास और हीलिकाप्टर राइडिंग मद में प्रतिदिन खर्चने वाले विदेशी भी आकर देश में विदेशी पूंजी बढ़ा रहे हैं। कहीं न कहीं यह संतई से सियासी सफर तय करने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर और सूबे के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता का परिणाम है। संभव है कि यह भी एक तरह से उनकी सियासत का हिस्सा हो।

लेकिन जो भी हो आज जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहुँच रहे हैं उनके श्रीमुख से एक बात अवश्य निकल रही है जय हो योगी। उसका सीधा सपाट कारण है। अनादि काल से आयोजित हो रहे इस कुम्भ के संदर्भ में जो साक्ष्य मिलते हैं उस लिहाज से 7 वीं शताब्दी में भ्रमण पर भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि राजा हर्षवर्धन ने उस समय गंगा तट पर धर्म सभा का

आयोजन किया था। मध्यकालीन इतिहास में 9 वीं से 18 वीं शताब्दी के बीच अखाड़ों द्वारा कुम्भ आयोजन के संदर्भ मिलते हैं। इस तरह हर छः साल पर अर्ध कुम्भ और बारह साल पर कुम्भ का आयोजन होता है। बारहवें कुम्भ के आयोजन को महाकुंभ कहा जाता है। 2025 कुम्भ को भी इसीलिए महाकुंभ कहा गया क्योंकि यह 144 वर्षों बाद हो रहा है।

ऐसे में ऐसी सियासत जो सत्ता सहित आमजन को सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला साबित हो तो निःसंदेह इसका स्वागत होना चाहिए। जैसे युद्धकाल में सियासी मतभेद भुला सियासी दल सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। उसी तरह ऐसे कुम्भ सरीखे आयोजनों में भी सियासी दलों को एकजुट होकर सत्ता की व्यवस्था के सुचारु संचलन में सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। इससे देश से बाहर के देशों में न केवल देश की छवि निखरेगी बल्कि एक अपरिभाषित माध्यम से ठोस विदेशी पूंजी के देश में आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मिलने वाला आर्थिक आधार न केवल देश को मजबूती देगा बल्कि देश को समृद्धिशाली देश की कतार में खड़ा करने में सहायक होगा।



'फायर गर्ल' माहिरा शर्मा की बोल्ड तस्वीर पर फैंस बोले- 'बेबी डॉल, तुम कमाल कर रही हो!'

सलमान खान के चर्चित शो बिग बॉस से कई लोग रातों-रात स्टार बन जाते हैं, और ऐसा ही हुआ बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा के साथ। शो के दौरान अक्सर ट्रोल होने वाली माहिरा इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और वजह है उनकी कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें, जो सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं!

माहिरा का नाम शो के दौरान पारस छाबड़ा से जुड़ा था, और भले ही वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रही हों, लेकिन उनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। माहिरा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों के लिए तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं। इस बार तो उन्होंने अपने फैंस के दिलों की धड़कनें और भी तेज कर दी हैं!

सीधे बाथरूम से माहिरा की बैकलेस अवतार में कुछ हॉट तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। शीशे पर हाथ रखकर दिए गए सेक्सी पोज में माहिरा का अंदाज देखने लायक है। फैंस ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है- किसी ने लिखा, "मसला क्वीन हमेशा फायर रहती है," तो किसी ने कहा, "बेबी डॉल, तुम कमाल कर रही हो!"

किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी



ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है और आपको बता दें कि हाल ही में प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में उन्होंने संन्यास ले लिया। वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। इसी के चलते लगातार ममता कुलकर्णी काफी चर्चा का विषय भी बनी हुईं नजर आ रही हैं। लेकिन अब इसी बीच ममता कुलकर्णी का एक वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने एनडीटीवी के साथ में बातचीत की और यहां पर काफी सारे विवादित राज खोले हैं। इस पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि छोटा राजन के साथ में उनका कोई रिलेशनशिप था या नहीं।

निमृत कौर अहलूवालिया

बॉलीवुड डेब्यू करने के लिए हैं तैयार?

अपनी पंजाबी फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करने की खबरों के बाद, अब ऐसा माना जा रहा है कि निमृत कौर अहलूवालिया कपिल शर्मा की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' के बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'किस किस को प्यार करूं 2' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं।

टेलीविजन दर्शकों के बीच अपनी जबरदस्त लोकप्रियता के लिए जानी जाने वाली निमृत के फैंस काफी समय से उनके बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री के एक सूत्र ने इस पर कहा, 'निमृत कौर अहलूवालिया के 'किस किस को प्यार करूं 2' की कास्ट में शामिल होने पर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनका नाम एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने आया है। उनकी लोकप्रियता और आकर्षण को देखते हुए, वे फिल्म की कास्ट के लिए एक बेहतरीन जोड़ साबित हो सकती हैं।'

अगर यह सच है, तो निमृत इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल का हिस्सा बन सकती हैं, जो हंसी और मनोरंजन से भरपूर होने का वादा करती है। खासकर कॉमेडी जैसे जॉनर में निमृत को एक नए अवतार में देखने की संभावना ने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है।



इसरो का स्पेडेक्स इस कीर्तिमानी सफलता के मायने



संजय श्रीवास्तव

डॉकिंग में सफलता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अंतरिक्ष अब भारत मानव सहित चांद पर पहुंचने, वहां से नमूने लाने, अंतरग्रही अभियानों, और अंतरिक्ष में अपना स्टेशन निर्मित करने की योजना को समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा। एक सफलता कई मनोरथ पूरा कराने वाली सिद्ध होगी।

इसरो को सलाम...

इसरो ने देश को गर्व का एक और अवसर प्रदान किया है। पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबने उसका यह कीर्तिमानी कमाल देखा जब उसने अपने स्पेडेक्स अर्थात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, और आखिरकार अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट या उपग्रहों को एक साथ जोड़ने में कामयाब पा ली। हालांकि जुड़ने के बाद इन दोनों के बीच विद्युत आपूर्ति तथा फिर सफलता पूर्वक अलग करने का काम अभी बाकी है, पूरी उम्मीद है वह भी शीघ्र ही सफलतापूर्वक संपन्न होगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में एक अंतरिक्ष यान से दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग और अलग होने की स्थिति को अनडॉकिंग कहते हैं। भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनो के यह लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक अब रूस, अमेरिका, चीन के बाद संसार में सिर्फ अपने पास है। ठीक है कि विश्व की तीन

महाशक्तियां अमेरिका ने यह कारनामा 58 साल, रूस ने 57 और चीन ने 13 बरस पहले कर लिया था पर भारत की यह सफलता इसलिए प्रशंसनीय है कि जब अंतरिक्षीय सहयोग से संबद्ध तमाम अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों और समझौतों के बावजूद किसी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी या देश ने भारत से इस जटिल प्रणाली और तकनीक प्रक्रिया को साझा नहीं किया तो हमने अपनी स्वदेशी डॉकिंग मैकेनिज्म को विकसित किया और इसे 'भारतीय डॉकिंग सिस्टम' दे कर इसपर अपना पेटेंट लिया। हमने रूस, अमेरिका, चीन से अधिक उन्नत और किंचित अलग अंतरिक्षीय तकनीक के साथ इस परीक्षण को अंजाम दिया है। बस कुछ कदमों बाद जब इसके बाकी जटिल



मन्युवरिंग के पूरे होने की खबर आयेगी तब अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी जमीन और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस अभियान की सफलता के बिना अंतरिक्ष में चंद्रयान-4, मंगल यान, गगन यान के द्वारा अंतरिक्ष में मानव यात्री भेजना, अपने बूते भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बनाने उसे कार्यरत होने अथवा चांद या अन्य ग्रहों से नमूने लाने की अथवा अंतरिक्ष में एक से ज्यादा रॉकेट प्रक्षिप्त करने की कवायद जो विशेषकर बड़े अंतरिक्ष मिशनो के लिए महत्वपूर्ण है, इस जैसी हमारी तमाम अंतरिक्षीय महत्वाकांक्षा का पूरा होना कठिन था। अब इस परीक्षण की

सफलता ने कई मनोरथ एक साथ सिद्ध करने का रास्ता आसान कर दिया है। इससे तकनीक के मिल जाने के बाद कक्षा में ही किसी उपग्रह की गड़बड़ी सुधारने और वहीं किसी भी स्पेसशिप की रीफ्यूलिंग का तरीका भी मिलेगा। यह सफलता इसरो का आत्मविश्वास और बढ़ाएगा तथा अंतरग्रही अभियानों, उन्नत अंतरिक्ष खोजों, भविष्य के चंद्रमा मिशनो, ग्रहों के बीच प्रवास के लिए भी पथ प्रशस्त करेगा।

बीते साल इसरो ने अपने अगले डेढ़ दशक का ही रोडमैप जारी नहीं किया था बल्कि 2040 से 2047 तक की योजनाएं सार्वजनिक की थीं। इसमें अगले साल 2026-27 में गगनयान की दूसरी ह्यूमन फ्लाइट और 2028-29 में तीसरी ह्यूमन फ्लाइट के भेजने की बात है। उसक इरादा है कि 2029 तक तीन मानवयुक्त यान भेजे तथा इनकी सफलता के आकलन तथा आपेक्षित सुधार के बाद 2030 में आखिरी गगनयान मिशन -5 यानी ल्यूपेक्स के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुंचाया और वापस ले आया जाये। 2035 तक पांच मॉड्यूल वाला अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है, पहला मॉड्यूल साल 2028 में लॉन्च होगा इसके बाद बाकी। इन्हें अंतरिक्ष में एक साथ जोड़ना इसी तकनीक से संभव होगा। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने-आने तथा धरती से आपूर्ति पहुंचाने के लिये भी इस तकनीक की आवश्यकता रहेगी। 2037-38 में चंद्रमा की सतह पर भारतीय रोबोटिक ह्यूमनोइड उतारने की योजना इसरो ने तैयार कर ली है। वह 2040 में चंद्रमा पर मानव सहित यान भेजने, उसकी सतह पर पहला भारतीय कदम रखने और इसके बाद कू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराने की अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना में लगा हुआ है। अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर पहुंचाने या उससे पहले चंद्रयान-4 मिशन के तहत चंद्र नमूने लाने के लिए भी अंतरिक्ष में एक यान से दूसरे यान से अलग होना और उसके बाद वापस लौटने वाले यान से जुड़ना जरूरी है सो यह तकनीक उसके लिए भी अनिवार्य थी। अंतरिक्ष में जाम की वजह से 30 दिसंबर की रात स्पेडेक्स की लांचिंग में दो मिनट का विलंब हुआ था, समान कक्षा में उसी पथ पर कुछ दूसरे उपग्रह



भी मौजूद थे। अंतरिक्ष में कार्यक्षम के अलावा निष्क्रिय उपग्रहों की भी भारी भीड़ है। निजी कंपनी स्टारलिनक के 7 हजार संचार उपग्रह जल्द बढ़ कर 12 हजार पहुंचने वाले हैं तो हजारों दूसरे निष्क्रिय हो मलबे तौर पर हैं। इस अंतरिक्षीय कचरे की समस्या से निबटने में स्पेडेक्स परीक्षण एक समाधान बन सकता है। इसके सैटेलाइट रोबोटिक आर्म के जरिए किसी उपग्रह या क्यूबसेट को पकड़ कर अपनी ओर खींचा और न सिर्फ कक्षा में भटके उपग्रहों को सही जगह लाया जा सकता है बल्कि निष्क्रिय उपग्रहों के मलबे को दूर किया जा सकता है। स्पेडेक्स अभियान के दौरान वास्तविक परिस्थितियों में कुछ विशेष परीक्षण भी किए जाएंगे जैसे डॉकिंग के अंतिम चरण का परीक्षण करने के लिए डॉकिंग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस टेस्ट, नियंत्रित परिस्थितियों में डॉकिंग तंत्र का परीक्षण करने के लिए वर्टिकल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी और रीयल टाइम सिमुलेशन के साथ रेंडेजवस सिमुलेशन लैब जो इसके एल्गोरिदम को जांच सकेगा। इनके अलावा सटीक माप लेने वाले कई नए सेंसर जैसे लेजर रेंज फाइंडर, रेंडेजवस सेंसर और डॉकिंग सेंसर का परीक्षण भी लगे हाथ हो जायेगा, इसी दौरान एक नितान्त नए प्रोसेसर को भी आजमाया जाएगा। इस अभियान में साथ गए इसरो के 14 और गैरसरकारी संस्थाओं, स्टार्ट-अप और शैक्षणिक संस्थानों के 10 पेलोड अंतरिक्ष में विकिरण, के अलावा वहां की माइक्रोग्रेविटी संबंधित कई प्रयोग करेंगे। इन से करीब दो साल तक उपयोगी आंकड़े मिलते रहेंगे जो भविष्य के मिशनों के लिए ऑटोनॉमस सिस्टम बनाने के काम आएंगे। पहली बार मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड का इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों और वनस्पति की निगरानी के



लिए करते हुए जैविक प्रयोग के तहत वहां लोबिया के 8 बीज उगाए जाएंगे, पौधे की बढ़त आंकी जाएगी।

इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत दो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक दूसरे को नियत दूरी पर रखकर एक को टारगेट और दूसरे को चेजर के तौर पर 7 जनवरी को जोड़ने का तय किया था, लेकिन इसे टाला, फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टली यहां तक कि 12 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। तब यह कयास था कि अब डॉकिंग कहीं मार्च में ही संभव हो पाये पर धरती से 470 किलोमीटर दूर, किसी बुलेट की तकरीबन दसगुना यानी 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काटते उपग्रहों को जमीन से नियंत्रित कर, डॉकिंग करने के साथ अंततः इसरो ने अपने कौशल से एक इतिहास बना दिया। अब बचता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर का काम और फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग। अब आगे इसरो के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है 2047 से पहले रीयूजेबल रॉकेट बना लेना। निस्संदेह उसकी प्रगति को देखकर यह सफलता भी निश्चित लगती है। फिलहाल यह कामयाबी केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती सशक्त स्थिति को दर्शाता है बल्कि ये देश की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। विशेषतः उस दौर में जब अंतरिक्ष, वैश्विक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र बन गया हो और प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही हो।

DISTINCTIVE STYLE
THRILLING POWER



C A M R Y

POWERFUL.
LUXURIOUS.

Awesome



- ATTRACTIVE LOW INTEREST OF 5.99 %*
- COMPLIMENTARY EXTENDED WARRANTY*
- COMPLIMENTARY 5 YEARS ROADSIDE ASSISTANCE

RNI TITLE CODE : DELENG19447

You only hear the gushing sound...
Rest is all silent.

Style Series
Single Lever Basin Mixer

Experience it. Look at it from all angles. Check out the contours,
the craftsmanship, the perfection of form and the waterfall...

Glamour ■ Convenience ■ Technology


MARC[®]
Bathing Luxury

MARC SANITATION PVT. LTD.

A-2, S.M.A. Co-op. Industrial Estate, G.T. Kamal Road, Delhi-110 033

Ph: 27691410, Fax: 011-27691445/27692295 E-mail: info@marcindia.com Website : www.marcindia.com